RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक
अभिजीत कुमार, 9431006107
समाचार संपादक
अखिलेश कुमार, 9431089053
विशेष संपादक
मुकेश कुमार सिंह
सहायक संपादक
कोमल सुल्तानिया
राजनीतिक संपादक
प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337
संपादकीय सलाहकार
राजीव कुमार सिंह 9431210181
कॉन्सेप्ट एडिटर
अनूप कुमार शर्मा, 7004821433
राजनीतिक ब्यूरो
अमरेंद्र शर्मा 9899360011
प्रभाकर कुमार राय
प्रबंधक
अविनाश कुमार 8287266244
विधि सलाहकार
वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट
बिहार ब्यूरो
अनूप नारायण सिंह 9546224277
क्राइम ब्यूरो
एसएन श्याम
मुख्य संवाददाता
सोनू सिन्हा,9431006189
आशीष कुमार
जिला ब्यूरो
बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316
अमित सिंह, 9430595995
भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334194515, 7677093032
समस्तीपुर : राजेश कुमार
चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993
मुंगेर : सिद्धांत
कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता 9973077043
सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)
बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877
दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841
स्वाति, रंजीत कुमार
ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318
प्रधान कार्यालय
गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)
मो.- 9431006107, 9939815347
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख
राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी भाजपा

जय जयराम सिंह
JJRS CONSTRUCTION PT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 9, अंक : 7, जनवरी 2023, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

07 यहां चिता की तपिश पर होती है साधना...

जीर्णोद्धार की आस में टूट रही ... 10

बहुआयामी गरीबी और शोषण ... 18

राहुल गांधी की अंग्रेजी-भक्ति? 13

दूध की सूखती धार 24

बेनकाब हुआ डब्ल्यूएचओ का झूठ

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

कोरोना संकट के तत्काल बाद स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने व जरूरतमंद देशों की मदद करने पर दुनिया में भारत की खूब वाहवाही हुई। भारत ने अनेक गरीब मुल्कों को संकट से उबरने के लिये जीवन-रक्षक उपकरण उपलब्ध कराये। तब भी डब्ल्यूएचओ ने भारतीय वैक्सीन को मान्यता देने में अनावश्यक विलंब किया। वहीं अब अफ्रीकी देश गाम्बिया में जब बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हुई तो आरोप लगा कि हरियाणा की एक दवा कंपनी के सिरप के सेवन से ये मृत्यु हुईं। विडंबना यह है कि आरोप संयुक्त राष्ट्र की संस्था डब्ल्यूएचओ ने लगाये। दुर्भाग्यपूर्ण यह कि बिना किसी जांच के ये आरोप भारतीय दवा कंपनी पर मढ़े गये। भारत विरोधी पश्चिमी मीडिया ने इस खबर को खूब रस लेकर छापा। अब भारत सरकार ने जांच में पाया कि गाम्बिया में बच्चों की मौत में भारतीय कंपनी के सिरप की कोई भूमिका नहीं थी। बिना किसी ठोस आधार के ऐसे बेतुके आरोप लगाने पर भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ को आड़े हाथ लिया है। भारत सरकार ने इस बाबत आधिकारिक आपत्ति जताई है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने जांच के बाद पाया कि गाम्बिया में बच्चों की मौत में सिरप का कोई लेना-देना न था। हालांकि, इससे पहले बीते माह गाम्बिया की सरकार कह चुकी थी कि बच्चों की मौत से भारतीय दवा निमार्ता कंपनी के सिरप का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डब्ल्यूएचओ के आरोपों से भारतीय फार्मा कंपनियों की छवि को हुए नुकसान की भरपाई हो पायेगी? निस्संदेह, दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था की इस तरह की गैर-जिम्मेदार बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इसके मूल में भारत विरोधी ताकतों की साजिश थी? यदि हां तो उसकी जांच की जानी चाहिए। हाल के वर्षों में अफ्रीका व गरीब मुल्कों में भारतीय दवा कंपनियों की अच्छी पहचान बनी है। एक तो दवाएं सस्ती हैं, वहीं कारगर भी। इस लोकप्रियता से बौखलाई भारत विरोधी ताकतों ने गाम्बिया की घटना के जरिये भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। दरअसल, पश्चिमी देशों की महाकाय दवा निमार्ता कंपनियां विकासशील देशों में अपने कारोबार को मिलने वाली किसी भी चुनौती के खिलाफ ऐसी साजिशें रचती रहती हैं। जिनसे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को लेकर है, जिसने बिना किसी जांच के आरोप भारतीय दवा कंपनी पर लगा दिये। सर्वविदित है कि पूरे कोरोना संकट के दौरान डब्ल्यूएचओ पूरी तरह से नाकाम हुआ। वह कोरोना वायरस के मूल स्रोत का पता नहीं लगा सका। कहा तो यहां तक गया कि इसके प्रमुख की नियुक्ति में चीन की भूमिका रही जिसके चलते प्रमुख ने कोरोना संकट के बाद दुनिया के निशाने पर आये चीन का बचाव किया। निस्संदेह, अपनी तमाम नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह संगठन बेतुकी बयानबाजी का सहारा ले रहा है। बहरहाल, भारतीय दवा कंपनियों को भी इस घटना के बाद सतर्क होकर अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

भारत विरोधी पश्चिमी मीडिया ने इस खबर को खूब रस लेकर छापा। अब भारत सरकार ने जांच में पाया कि गाम्बिया में बच्चों की मौत में भारतीय कंपनी के सिरप की कोई भूमिका नहीं थी। बिना किसी ठोस आधार के ऐसे बेतुके आरोप लगाने पर भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ को आड़े हाथ लिया है। भारत सरकार ने इस बाबत आधिकारिक आपत्ति जताई है।

नीतीश का नया दांव तेजस्वी को 2025 में ताज

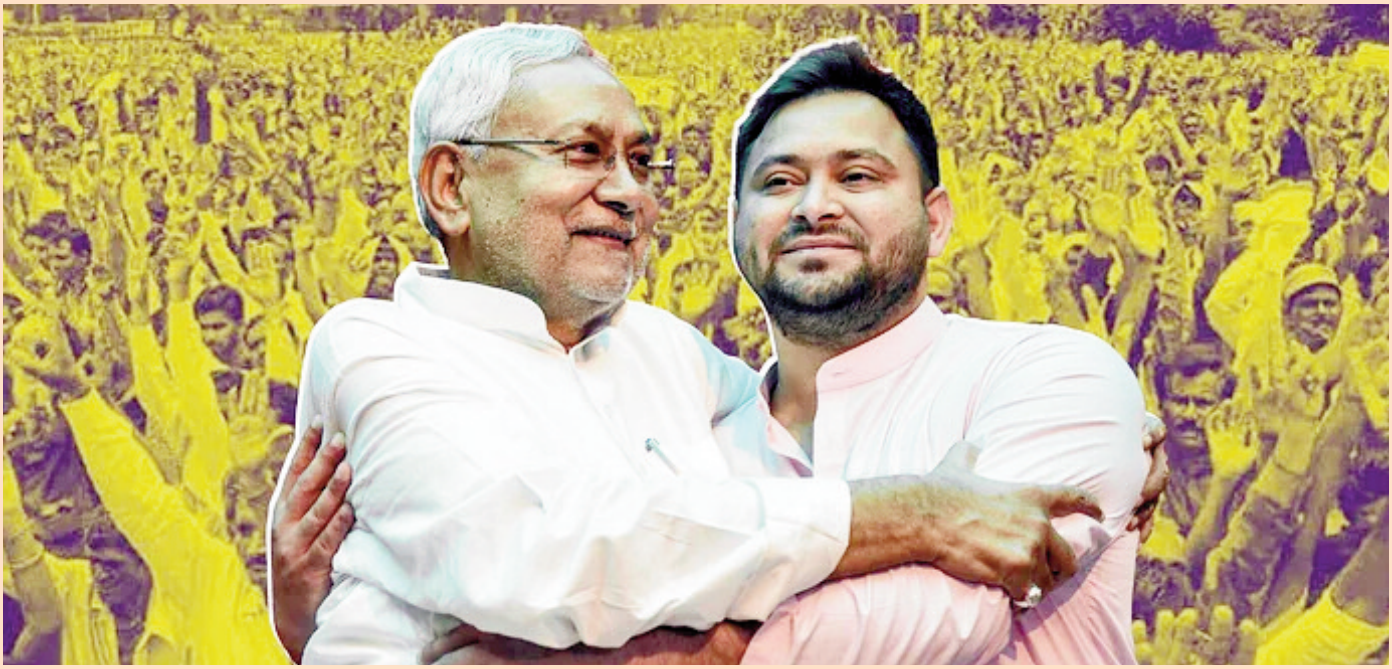

राजद व जदयू में शह-मात का खेल जारी

नीतीश के बयान से जदयू के नेता भी चकित

राजद के मांग को तीन वर्षों के ठंडे बस्ते में डालने सफल प्रयास

अखिलेश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2023 आगमन के पूर्व लालू प्रसाद यादव के पुत्र और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का नेता घोषित कर एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास किया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषको के साथ हीं राजद व जदयू के शीर्ष नेता भी चकित नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के इसी राजनीतिक बाजीगरी के कारण चाणक्य की उपाधि दी जाती है और वे संख्या बल में राज्य में तीन नम्बर पर होने के बावजूद जब चाहते हैं तब गठबंधन की नई नई गांठ बनाकर बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने में सफलता हासिल कर लेते हैं।

बिहार विधानसभा उप चुनाव में कुढ़नी विधानसभा के महागठबंधन से जदयू उम्मीदवार की हुई हार के बाद विपक्षी दलों के साथ हीं गठबंधन के नेता भी नीतीश कुमार के उपर ऊँगली उठा रहे थे। और गठबंधन में उनके नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा करते हुए राजद के नेताओं ने तेजस्वी को सत्ता सौपने की वकालत भी करने लगे। कयास यहाँ तक लगाया जाने लगा कि खरमास समाप्त होते हीं आगामी 14 जनवरी के बाद कभी भी तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ले सकते हैं। पिछले अगस्त में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का सरकार बनने के बाद बिहार में विधानसभा के तीन सीटों पर उप चुनाव में दो पर भाजपा जीत हासिल की, जबकि मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी राजद के टिकट पर जीती। मोकामा में जीत का श्रेय अनंत सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव का परिणाम बताया गया। वहां नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने भी नहीं गये थे। वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यह कह रहे थे कि " नीतीश कुमार को घोषणा के अनुसार लग रहा है कि 2022 बितने के बाद 2023 में देश की लडाई लडेंगे और तेजस्वी को बिहार सौंप देंगे। देश नीतीश और बिहार तेजस्वी का इंतजार कर रहा है।" वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश द्वारा तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप कर आश्रम चले जाने का वयान दिया गया था।

कुढ़नी और गोपालगंज में महागठबंधन की हार तथा सरकार में शामिल दलों के नेताओं की वयानबजी से हो रहे चौतरफा हमले पर बिहार विधानसभा सत्र आरंभ होने से दो दिनों पूर्व नीतीश कुमार ने अपने गृह जिला नालंदा के भगनबिगहा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 'इतना तो हमलोग काम कर हीं रहे हैं, बाकी जो कुछ आगे होगा उसे तेजस्वी यादव पुरा करेगे और कारवाई करेंगे, आगे लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।' इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा और तेज हो गया कि नव वर्ष में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। लेकिन उसके ठीक दुसरे दिन विधानसभा सत्र आरंभ होने से पूर्व संध्या पर महागठबंधन की बैठक के दौरान नीतीश कुमार यह घोषणा किया कि 'महागठबंधन 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व के नेतृत्व में लड़गा।' इस बयान के उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास किया है। वह यह कि 2025 तक तो मैं मुख्यमंत्री हूँ। अब कम से कम तीन वर्षों तक उनके कुर्सी को लेकर राजद के तरफ से वयानबजी नहीं होगा। इससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में बिहार की महागठबंधन लडेगा और राजद के सहारे लोकसभा में ज्यादा सीटें हांसिल करने के बाद राष्ट्रीय राजनीति करने में बल मिलेगा। साथ हीं 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम का आकलन कर फिर अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। नीतीश कुमार के इस दांव के बाद प्रमुख सहयोगी और विधानसभा में संख्या बल में सबसे बड़ा दल राजद तो शांत रहेगा हीं, साथ हीं लोकसभा चुनाव तक महागठबंधन की यदि मजबुती कायम रहा तो फिर भाजपा के लिए भी डगर आसान नहीं होगा।

कुढ़नी के कोख से निकली बिहार की नई सियासत

अनूप नारायण सिंह

बिहार में हाल के दिनों में तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए. इन तीनों सीटों के उपचुनाव को बिहार में हाल में बने महागठबंधन की स्वीकार्यता का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था. इस लिहाज से देखें तो बिहार ने महागठबंधन को खारिज किया है, क्योंकि मोकामा की जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि एक व्यक्ति अनंत सिंह की जीत थी. सात दलों के महागठबंधन के बावजूद,अकेले भाजपा ने पहले गोपालगंज और फिर कुढ़नी में जीत दर्ज की. भाजपा की इस जीत ने उस राजनीतिक विश्लेषण पर ही मुहर लगाई है जो इस चुनाव को महागठबंधन की स्वीकार्यता या और अस्वीकार्यता के रूप में देख रहा था. फिर दूसरा सवाल यह भी है क्या बिहार में तीन उपचुनाव के परिणाम सिर्फ महागठबंधन के खिलाफ है या फिर आक्रोश नीतीश कुमार को लेकर भी है? क्योंकि इन तीन चुनाव में मोकामा में राजद प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने अपनी सीट बचा ली, गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन जिस कुढ़नी की सीट को अति विश्वास में नीतीश कुमार ने राजद से उसकी सिटिंग सीट मांग कर चुनाव लड़ा, वहां भी हार गए.वो भी तब,जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले ना तो गोपालगंज में चुनाव प्रचार को गए और ना ही मोकामा में लेकिन कुढ़नी में नीतीश कुमार ने तेजस्वी और अपने मंत्रिमंडल के लगभग सभी मंत्रियों के साथ मिलकर अपने उम्मीदवार के लिए बड़ी रैली भी की. महागठबंधन के सभी सात दलों के बड़े नेता कुढ़नी में लगातार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में कैंप किए रहे.

गोपालगंज चुनाव परिणाम हो या फिर कुढ़नी अब यह स्पष्ट हो चुका है कि राजद और जदयू के वोट एक दूसरे को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं. कुढ़नी में ही उदाहरण के रूप में देखें तो मुस्लिम बहुल चैनपुर वाजिद पंचायत में जहां 90% वोटिंग होती रही है वही इस बार मात्र 60 फीसदी वोटिंग हुई.

जिस मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां उपचुनाव में भाजपा की हार ने यह बताया कि भूमिहार भाजपा से नाराज हैं, उसी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी उपचुनाव ने यह भी बताया कि भूमिहार अभी भी भाजपा के परंपरागत वोट बैंक है.जबकि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट खुलकर मुकेश सहनी के भूमिहार उम्मीदवार नीलाभ कुमार के समर्थन में मैदान में था और मुकेश सहनी ने भी खूब माछ-भात के नारे लगाए, यानी कि भूमिहार और सहनी के एक होने के नारे लगे लेकिन सब वेअसर रहा.

गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो यह कहा गया कि वहां वोटकटवा की वजह से

भाजपा जीत गई. साधु यादव की पत्नी ने यादव वोट बैंक और ओवैसी के उम्मीदवार ने मुसलमान वोट में सेंधमारी की यानी कुल मिलाकर राजद के एमवाई समीकरण में सेंध लगी तो भाजपा जीत गई. लिहाजा कुढ़नी में नीतीश कुमार ने भाजपा के परंपरागत भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक भूमिहार, नीलाभ कुमार को मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का उम्मीदवार बना कर खड़ा कर दिया. यहां ओवैसी के उम्मीदवार मुर्तजा अंसारी भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन यह दोनों ही कुढ़नी में बेअसर रहे.श्क्ढ के भूमिहार उम्मीदवार को जो वोट मिले वो भूमिहार कम,मल्लाह ज्यादा हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के इस आक्रोश को झेलने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं?

जहरीले मदिरा से बिहार में बिछी लाशें

शराबबंदी कानून को लेकर संग्राम तेज

नीतीश ने सदन में मर्यादा की सीमा तोड़ा

विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी हुआ हमलावर

अखिलेश कुमार

बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून और उसे सख्ती से लागू करने की प्रतिबद्धता की कलई पुनः जहरीले शराब ने खोल दी। पूर्णतः शराबबंदी वाले बिहार राज्य के छपरा जिले में दो दिनों के भीतर तीन दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत के बाद जब 13 दिसम्बर को विधानसभा में भाजपा के सदस्यों ने आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुमार आपा खो बैठे और संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करते हुए अपशब्द का प्रयोग करने लगे। उन्होंने तमतमाते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के तरफ इशारा करते हुए बोला - अरे! तुम बोलेगा? भगाओ सबको, निकालो?

नीतीश कुमार ने सदन में एक मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह का आचरण 13 दिसम्बर को प्रस्तुत किया वैसा बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। उनके ऐसे कृत्य से उनके खुद का चार दशक से अधिक समय तक के शालीन और मर्यादित राजनीतिक जीवन पर दाग लगा दिया।

छपरा जिले के विभिन्न गांव में दो दिनों के भीतर जहरीले शराब पीने से विश्वकर्मा पटेल, सलाऊदीन, अजय गिरी, चन्देश्वर साह, जगलाल साह, अनिल ठाकुर, एकरामुल हक, सीताराम राय, दुधनाथ तिवारी, शैलेन्द्र राय, हरेराम, भरत साह , मोहम्मद नसीर, मनोज कुमार, कुणाल सिंह, दुधनाथ तिवारी, उपेन्द्र राम, उमेश राय, विक्की महतो आदि तीन दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में वर्ष 2016 में लागू पूर्णतः शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार धरातल पर उतारने में विफल रही है। शराब की बिक्री और बरामदगी राज्य के हर भागों में हो रहा है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जहरीले शराब पीने से बिहार में अबतक करीब एक हजार लोगों की मौत हो चुकी है।

इस कानून को धरातल पर उतारने में विफलता के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के साथ खुद अपने तथा सहयोगी दलों के भी निशाने पर आ गये हैं। सरकार में शामिल राजद, कॉंग्रेस, हम तथा समर्थन देने वाला सीपीआई एम एल के विधायक भी शराबबंदी कानून की आलोचना करते हुए इसकी समिक्षा करने की मांग कर रहे हैं।

राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र विधायक व पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कहा है कि यह कानून केवल कागज पर चल रहा है शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के नाम पर राज्य के विकास टैक्स में मिले राशि को पुलिस, वाहन, जेल, न्यायालय व अन्य के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाने पीने के चीज पर प्रतिबंध नीतीश कुमार

के मानसिक दिवालियेपन का परिणाम है। उन्होंने जहरीले शराब से मौत को नरसंहार करार देते हुए कहा कि अधिकारियों के माध्यम से पैसा लूट का इसे माध्यम बनाया गया है।

वहीं कॉग्रेस विधायक दल के नेता भी कहा कि बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है। बिहार के अधिकारी शराब तस्करों से मिले हुए हैं। खुद नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के विधायक डॉ संजीव कुमार शराबबंदी कानून को विफल बताते हुए इसकी समिक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस कानुन के आड़ में खासकर दलित व पिछड़ों का दमन किया जा रहा है। नीतीश सरकार को समर्थन देने वाले दल भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल तथा सुदामा प्रसाद ने जहरीले शराब से मरने वाले लोगों के आश्रितों को दस दस लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की।

इधर नीतीश कुमार के करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के जिद्द के कारण आज बिहार की यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मैं दो वर्षों तक रहा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके साथ रहने वाले भी प्रतिदिन शराब पीते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा और राजद वाले जब नीतीश के साथ सत्ता में रहते हैं तो चुप हो जाते हैं तथा विपक्ष में आते ही हायतौबा मचाने लगते हैं। शराबबंदी कानून की विफलता तथा जहरीले शराब पीने से मौत का मामला भाजपा सांसदों ने 14 दिसम्बर को संसद में भी उठाया।

वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून की समिक्षा करने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो शराब पीएगा वो मरेगा। यह कानून हर हाल में लागू रहेगा और मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

वहीं कॉग्रेस विधायक दल के नेता भी कहा कि बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है। बिहार के अधिकारी शराब तस्करों से मिले हुए हैं। खुद नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के विधायक डॉ संजीव कुमार शराबबंदी कानून को विफल बताते हुए इसकी समिक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस कानुन के आड़ में खासकर दलित व पिछड़ों का दमन किया जा रहा है। नीतीश सरकार को समर्थन देने वाले दल भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल तथा सुदामा प्रसाद ने जहरीले शराब से मरने वाले लोगों के आश्रितों को दस दस लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। इधर नीतीश कुमार के करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के जिद्द के कारण आज बिहार की यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मैं दो वर्षों तक रहा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके साथ रहने वाले भी प्रतिदिन शराब पीते हैं।

नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में भाजपा

बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्दी ताजपोशी होने वाली जिसको लेकर कई नामों पर विचार मंथन चल रहा है बिहार के सियासी समीकरण व दूसरे दलों के जातीय समीकरण पर भी पार्टी की नजर है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो दीघा से भाजपा विधायक संजीव चौरसिया के नाम पर काफी हद तक सहमति बन चुकी थी पर कांग्रेस जदयू जैसे पार्टियों के सियासी समीकरण को देखते हुए भाजपा का एक बड़ा वर्ग महाराजगंज से सांसद तथा राजपूत बिरादरी से आने वाले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है भाजपा अगड़ा चेहरा रख कर पिछड़ा वोट बैंक की राजनीति बिहार में करना चाहती है अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है। अगर इन दोनों नामों पर किंतु परंतु की स्थिति बनी तो बैकुंठपुर से भाजपा के विधायक रहे तथा ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले मिथिलेश कुमार तिवारी पार्टी की पसंद बन सकते हैं।

बिहार के एक आईपीएस अधिकारी ऐसे भी जो बन गए मिसाल

अनूप नारायण सिंह

राकेश सिंह पेशे से अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लिखते है की मैं बिहार के एक राजनीतिक दल जेडीयू का जिला मुख्य प्रवक्ता भी हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं बगहा के तत्कालीन सांसद श्री कैलाश बैठा का निजी सचिव हुआ करता था। 2004-05 की बात है जब बिहार में कथित जंगल राज की समाप्ति के बाद श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनी थी। दियारा इलाके में कुशवाहा जाति के तीन किसानों की दस्यूओं ने हत्या कर दी थी। इस घटना के तुरत बाद तत्कालीन एसपी बालदेव प्रसाद का स्थानांतरण हो गया और श्री विकास बैभव, आईपीएस को बगहा का नया एसपी बनाया गया। श्री वैभव ने आते ही अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ भर दिया। उनकी ईमानदार छवि, पेशेवर कार्यशैली, सुचना तंत्र और छापेमारी ने दस्यूओं को दर-दर भागते रहने को मजबूर कर दिया।

इससे पूर्व बगहा एसपी रत्न संजय ने दस्यूओं में खौफ पैदा किया था और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। ठीक यही काम अब विकास वैभव सर कर रहे थे। इनका तरीका थोड़ा अलग और अधिक प्रभावशाली था जब इन्होने दस्यू सरदारों की आर्थिक कमर तोड़ने पर काम शुरू किया। उस वक़्त चम्पारण को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। जिले के दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ रैयती और सरकारी भूमि पर दस्यूओं ने अवैध कब्जा कर गन्ने की खेती की थी जो उनकी आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार था। इसी राशि का इस्तेमाल वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में करते थे। नए एसपी साहब ने इन गन्ने की फसल को पुलिस और प्रशासन की मदद से कटवाकर चीनी मीलों में इसकी आपूर्ति की और इससे आने वाली आय को सरकारी खजाने में जमा करना शुरू किया। दूसरी तरफ एसपी साहब की लगातार दबिश के बाद अपहरण, लेवी व फिरौती का धंधा लगभग बंद सा हो गया और गन्ने से होने वाली आय भी बंद हो गई। तब अपराधियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया था। इसी वक़्त बिहार की नई सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ बताते हुए विकास वैभव सर ने कई दुर्दन्त अपराधियों को आत्मसमर्पण करा मुख्य धारा में लौटने को मजबूर कर दिया। इस कड़ी में चम्पारण में आतंक का पर्याय माने जाने वाले दुर्दांत दस्यू सरगना बासदेव यादव का नाम प्रमुख है। इसके साथ ही चम्पारण से नक्सलियों के खात्मे का श्रेय भी विकास वैभव सर को जाता है। इस दौरान एसपी साहब के स्थानांतरण की खबर के बाद प्रशासन के कुशल व निष्पक्ष संचालन में बाधक बन रहे उस वक़्त के दबंग राजनीतिक शख्सियत को उनके ही क्षेत्र में जनता द्वारा भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। जाँच पदाधिकारी के समक्ष एसपी साहब के समर्थन में बगहा की पाँच हजार से ज्यादा स्थानीय जनता उमड़ पड़ी थी जो उनकी लोकप्रियता को दशार्ती थी। इसी का प्रतिफल है कि लोगों ने उनकी यादें सहेजने के लिए बगहा में उनके नाम पर एक चौराहे और सड़क का भी नाम रख दिया। ऐसा किसी पदाधिकारी के लिए जनता के अगाध प्रेम को दशार्ने वाली जिले के इतिहास की यह पहली घटना है।

तब के एसपी और अब के आईजी विकास वैभव सर युवाओं के भी प्रेरणास्त्रोत हैं जिनसे राज्य और राज्य से बाहर के हजारों छात्र व युवा प्रेरित होते हैं। इन्होने 'लेट्स इंस्पायर बिहार' के नाम से एक अभियान भी चलाया है जो अपने कार्यक्रमों के जरिये युवाओं को बिहार के गौरवशाली अतीत का स्मरण कराता है और उससे इंस्पायर होने के बाद जीवन में नई राह, संस्कार और बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यार्थियों को कैरियर टिप्स और प्रेरणादायक सम्बोधन के जरिये विकास वैभव सर उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार करते हैं। विभिन्न विधाओं में पारंगत प्रतिभाओं

को निखार कर जनता के सामने लाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना और उनके स्वाभिमान को आसमान देना ही लेट्स इंस्पायर बिहार का मुख्य लक्ष्य है। सैकड़ों छात्र/छात्राएँ, युवा, स्टार्ट अप उद्यमी, बुद्धिजीवी, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता विकास वैभव सर के इस मिशन से जुड़ रहे जो बिहार के उज्ज्वल भविष्य को एक नई ऊंचाई देने वाला है। इस अभियान को हमारी शुभकामनायें।

राजद कोटे से भूरा बाल साफ ?

अनूप नारायण सिंह

बिहार की मौजूदा महा गठबंधन सरकार में राजद कोटे से अब कोई भी सवर्ण मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। कभी भूरा बाल (भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और लाला) की खिलाफत कर एमवाई (मुस्लिम यादव) समीकरण के बल पर बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाली राजद ने खुद को ए टू जेड की पार्टी होने का खूब दंभ भरा। पर सत्ता में वापसी होते ही अपने पुराने ढर्रे पर लौट गई है। मौजूदा सरकार में भूमिहार कोटे से अनंत सिंह के करीबी एमएलसी कार्तिक सिंह को पहले कानून मंत्री फिर गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया अपराधिक मामले के चलते उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा दूसरी तरफ राजपूत जाति से आने वाले सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया सुधाकर सिंह लगातार अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे थे उन्होंने अपना इस्तीफा अपने दल के नेता तेजस्वी यादव को भेजा था उनके पिता जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष है इन दोनों को भरोसा था कि तेजस्वी सुधाकर सिंह द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे पर उल्टे तेजस्वी ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा नीतीश कुमार को भेजा और नीतीश कुमार ने सीधे उसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया ऐसे में सुधाकर सिंह की राज्य मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। राजद कोटे से किसी ब्राह्मण या कायस्थ को मंत्री नहीं बनाया गया था अब कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद राजद के मंत्रियों की लिस्ट सवर्ण विहिन हो गई है। बिहार में मौजूदा समय में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है यह विधानसभा क्षेत्र है मोकामा और गोपालगंज मोकामा भूमिहार बहुल क्षेत्र है जबकि गोपालगंज राजपूत बहुल ।मोकामा सीट राजद के ही विधायक अनंत सिंह के एक आपराधिक मामले में दोषी होने के बाद खाली हुई है जबकि गोपालगंज सीट भाजपा के सुभाष सिंह के निधन के कारण।

अब राजद को लेकर राजद की फोटो में ही दुविधा है जो अपर कास्ट के वोटर है वह राजद का असली गेम प्लान समझने लगे हैं कि किस तरह से ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करने वाली राजद ऊंची जातियों को दरकिनार करने में लगी है हालांकि राजद से जुड़े सूत्र बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है फिर राज्य मंत्रिमंडल में किसी राजपूत भूमिहार का मंत्री नहीं होना एक बड़ा सवाल उठाता है सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद कई राजपूत चेहरे हैं जो राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह का। सुनील कुमार सिंह लालू परिवार के सबसे विश्वसनीय लोगों में शामिल है। ब्राह्मण कोटे से राजद थिंक टैंक में शामिल शिवानंद तिवारी के विधायक पुत्र राहुल तिवारी तथा सिवान के बड़हरिया से विधायक बच्चा जी पांडे मंत्री पद के प्रबल दावेदार है भूमिहार कोटे से राजद का कोई विधायक नहीं है ऐसे

में चुनाव जीत कर आए दो एमएलसीयो की किस्मत का ताला खुल सकता है हालांकि चर्चा यह है कि अगर मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीतती हैं तो उन्हें भूमिहार कोटे से मंत्री बनाया जाएगा। राजद से कोई कायस्थ विधायक एमएलसी नहीं है फिर भी दो-चार करीबी लोग हैं जिन पर तेजस्वी की नजर है। जिनमें विनोद श्रीवास्तव का नाम काफी चर्चा में है। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी महा गठबंधन सरकार में राजद कोटे की सभी मलाईदार विभाग तेजस्वी यादव ने खुद अपने पास रखा है।

खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राजद फिर से मुस्लिम यादव समीकरण के तरफ तेजी से बढ़ रही है। राजद को बिहार के अपर कास्ट के वोटरों पर भरोसा नहीं है।बिहार के सत्ता में वापसी के बावजूद जो प्रतिनिधित्व अपर कास्ट को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर भी चचाओं का बाजार गर्म है खबर है कि जगदानंद सिंह भी राजद के इस नई कार्यशैली से खुश नहीं है हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए कई बड़े नेताओं को लगाया गया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मिशन तेजस्वी की राह में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। राजद के तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं को तेजस्वी के सीएम बनने संबंधी बयान देने पर रोक लगा दी गई है। राजपूत और भूमिहार कोटे की खाली हुई मंत्री पद पर नए चेहरों की तैनाती नहीं होने से संशय की स्थिति बनी हुई है। मीडिया सूत्रों के अनुसार पार्टी से नाराज चल रहे जगदानंद सिंह ने भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने का मूड बना लिया है। जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन के मामले पर भी राजद की चुप्पी गलत संदेश दे रही है उत्तर बिहार में राजद का सबसे बड़ा चेहरा प्रभुनाथ सिंह का है। उनके भाई केदारनाथ सिंह लगातार तीसरी बार बनियापुर से विधायक हैं।

उनको भी मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर प्रभुनाथ समर्थक निराश है राजपूत जाति से हीं आने वाले चेतन आनंद रामा सिंह की पत्नी रणविजय सिंह समेत कई ऐसे चेहरे हैं जो राजद कोटे से मंत्री बनने की दौड़ में हैं। पर सूत्र बताते हैं कि अगर राजपूत कोटे से मौजूदा मंत्रिमंडल में कोई नई इंट्री होगी तो वह नाम राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह का हो सकता है जो कृषि और सहकारिता मामले के जानकार हैं तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सर्वाधिक विश्वस्त लोगों में शामिल है। राजद के लिए अपना सबकुछ समर्पित करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह महाराजगंज के सांसद रहे उमाशंकर सिंह विजय कृष्ण जैसे समर्पित राजपूत नेताओं के साथ जो कुछ हुआ उसे भी भुलाया नहीं जा सकता मौजूदा समय में राजद की राजनीति में भले प्रभुनाथ सिंह आनंद मोहन का परिवार राजद के प्रति समर्पित हो पर राजद के अंदर इन दोनों को लेकर भी संशय की स्थिति है। महागठबंधन की सरकार बन जाने के बाद अब कोई आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। राजद के अंदर राजपूत राजनीति एमएलसी सुनील कुमार सिंह के इर्द-गिर्द घूम रही है सुनील कुमार सिंह ने कई राजपूत चेहरों को पार्टी में शामिल कराया और विधानसभा के चुनाव में टिकट भी दिलवाया जिसमें अधिकांश ने सफलता भी पाई।

अब जबकि सुनील कुमार सिंह को ही मंत्री बनाए जाने में विलंब हो रहा है ऐसे में उनके स्वजातीय वोटरों में भी राजद को लेकर संशय की स्थिति कायम हो गई है। राजद में ब्राह्मणों के कई बड़े नेता हैं पर उन्हें भी उचित मान सम्मान नहीं मिल पाया है हाल ही में संपन्न पंचायत स्तरीय विधान परिषद चुनाव में राजपूत और यादव बहुल सारण से इकलौते ब्राह्मण चेहरे सुधांशु रंजन को टिकट दिया गया था पर पार्टी के एमवाई वाले समीकरण ने सुधांशु रंजन के खिलाफ ही भीतर घात कर दिया बावजूद इसके सुधांशु रंजन ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

छपरा जिला का माझी विधानसभा ब्राह्मण बहुल है अब ब्राह्मण मतदाता सुधांशु रंजन को माझी की दावेदारी पर मुहर चाहते हैं। सिवान वाले टुना पांडे लोकसभा टिकट का ख्वाब देख रहे हैं पर उनके राह में निवर्तमान जदयू सांसद कविता सिंह और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब बड़ा रोड़ा है। हालांकि महाराजगंज में अपने ही दल का सांसद होते हुए राजद ने प्रभुनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता पर दांव लगाने का भी साहस दिखाया था।

यहां चिता की तपिश पर होती है साधना...

बिहार के दरभंगा जिले में मां काली का यह भव्य मंदिर मौजूद है, जिन्हें यहां भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं. इस मंदिर के निर्माण की कहानी जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं. मां काली का यह मंदिर दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है. इस मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर एक खास स्थान पर आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह के चिता की तपिस को महसूस करते हैं, फिर चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों न पड़ रही हो.

यहां के लोगों का मानना है कि पूरे भारत में काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है. मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है. भक्तों को मां श्यामा के दर्शन से ही अदभुत सुख की प्राप्ति होती है. कहते है अगर भक्त नम आंखो से कुछ मांगते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है. इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवन शिव की जांघ एवं वक्षस्थल पर अवस्थित है. मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बायीं ओर भगवान गणेश और बटुक की प्रतिमाएं स्थापित हैं. चार हाथों से सुशोभित मां काली की इस भव्य प्रतिमा में मां के बायीं ओर के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में मुंड तो वहीं दाहिनी ओर के दोनों हाथों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान हैं.

मां श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है. माना जाता है कि जो भी मां की इस आरती का गवाह बन गया उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, साथ ही भक्तों की समस्त मनोकामना भी पूरी हो जाती है. मंदिर के गर्भगृह में जहां एक तरफ काली रूप में मां श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा ग्रह, नक्षत्रों सहित कई तान्त्रिक यंत्र मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में मां श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है. आमतौर पर हिन्दू रीती रिवाज के अनुसार यह परंपरा रही है की किसी भी व्यक्ति का कोइ भी मांगलिक संस्कार होने के एक साल तक वह श मशान नहीं जाता है, लेकिन मां श्यामा के इस मंदिर में नए जोड़े मां का आशीर्वाद ही लेने नहीं बल्कि श्मसान भूमि पर बने इस मंदिर अनेकों शादियां भी होती है.

जीर्णोद्धार की आस में टूट रही माझा गढ़ किले की सांस

अनूप नारायण सिंह

आमतौर पर राजा महाराजा रानी और भूत प्रेतों की कहानी आप को भी आकर्षित करती होगी ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के गोपालगंज जिले के माझा गढ़ की जहां का किला बिहार के मौजूदा सभी राजा रजवाड़ों के किले से अनूठा था इस किले के तीन तरफ पानी और एक तरफ जाने का रास्ता था प्राप्त जानकारी के अनुसार उन 1828 में माझा गढ़ के राजा कुमार माधव सुरेंद्र साही ने इस किले का निर्माण करवाया था राजा सुरेंद्र शाही ने अपने दुश्मनों से बचाव के लिए इस किले को उस जमाने में 9 मंजिला बनाया था और किले में कई तहखाने थे जिससे पानी के अंदर से ही ताहखाने के माध्यम से सैनिक गुप्तचर और राजा स्वयं किसी दूसरे किले में जा सकते थे स्थापत्य कला का यह वृहत नमूना राजमहल अपने आप में अनूठा था इस राजमहल को लेकर कई तरह की कहानियां भी इलाके में प्रचलित है प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 1934 में बिहार में आए भयंकर भूकंप किले के किले को ध्वस्त कर दिया और 9 मंजिले किले की 7 मंजिल इस भूकंप में ध्वस्त हो गई उसके बाद राजा सपरिवार दूसरे किले में चले गए और किले के दुर्दिन शुरू हो गए कहा जाता है इस किले के निर्माण को लेकर कई तरह के टोने टोटके किए गए थे कुछ लोग कहते हैं किले पर गिद्ध बैठ गया था इसी कारण से राजा ने इस किले को छोड़ दिया स्थानीय झंकार बना बताते हैं कि इस किले का निर्माण पहले कोईनी बाजार के पास होने वाला था जिसको लेकर तांत्रिकों के द्वारा टोना टोटका किया गया था और एक बड़े पोटली में चने की दाल को रख दिया गया था जिसे सियारों के समूह ने उठाकर जहां यह महल बना हुआ है वहां लाकर रख दिया और इसे शुभ माना गया और माना गया ईस जगह पर महल का निर्माण होगा और उसी जगह 1828 में बिहार के इस अनूठे 9 मंजिले किले का निर्माण हुआ अब इस किले में जहरीले सांप और जीव-जंतुओं का बसेरा है कई सारे बरगद के विशाल वृक्ष किले में उग आए हैं यह विशालकाय किला और इसकी कृति सिर्फ कथा कहानियों में जीवित है और अपनी अंतिम सांस गिन रहा है आज भी किले के चारों तरफ पानी है और एक तरफ से जाने का रास्ता है किले की देखरेख किसी के द्वारा नहीं की जाती है पर्यटक आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं पल-पल जमीनदोज होने की तरफ बढ़ रहे इस स्थापत्य कला के अनूठे धरोहर को बचाने के लिए ना राजघराने और ना ही जिला प्रशासन के तरफ से कोई पहल की गई है अगर समय रहते इस किले के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा तो यह पर्यटक और इतिहास भी दो को अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा।

आरक्षण के मामले में राजनीतिक दलों में गैर आरक्षित वर्ग एकजुट नहीं

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

आरक्षण बोतल का एक ऐसा जिन्न है, जिसे राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए निकालकर इस्तेमाल करना चाहते है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसके नुकसान फायदे के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा कभी विचार नहीं किया जाता है। विशेषकर देश और समाज को होने वाले नुकसान की, किसी भी दलों को चिंता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर, आरक्षण के मुद्दे पर मुहर लगा कर, राजनीतिक दलों का रास्ता और आसान कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों के लिए यह हॉट केक की तरह काम करने लगा है। किसी भी राजनीतिक दलों को इससे परहेज नहीं है। आरक्षण के विरुद्ध तो दूर क्रीमी लेयर के खिलाफ भी बोलने की साहस नहीं है। बल्कि आरक्षण के असली हकदारों के हिस्से पर कुंडली मारे बैठे है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक दलों के लिए हॉट केक है। किसी को भी इससे परहेज नहीं है। इसके खिलाफ बोलने का साहस किसी नेता या राजनीतिक दल में नहीं है।

आरक्षण ने देश को दो हिस्सों में बाँट दिया है आरक्षित और गैर आरक्षित। गैर आरक्षित वर्ग इसे अपने साथ अन्याय मानता है, किन्तु एक जुट नहीं रहने के कारण राजनीतिक दलों द्वारा बहुसंख्यक गैर आरक्षित आबादी की परवाह नहीं करती है, कहे तो बहुसंख्यक राजनेता भी, गैर आरक्षित बहुसंख्यक का स्वार्थ विभोर में, परवाह नहीं करते है। आरक्षण के मुद्दे से राजनीतिक दल इतना घबराते है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरक्षण का फायदा सही मायने में आरक्षित वर्ग को कितना हो रहा है, इसका आकलन कभी नहीं कराया गया है।

देखा जाय तो आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद से, यह संवैधानिक लाभ, चुनिंदा लोगों के हाथ में सिमट कर रह गया है। यही वजह है कि देश में आज भी सीवरेज में गैस निकलने से, दलित वर्ग के मजदूरों की मौत की खबरें, आती रहती है।

दलित हो या जनजाति, अभी तक अपने परंपरागत पेशा से, जुड़े हुए है। आरक्षण के बावजूद, बड़े वर्ग समूहों की सामाजिक-आर्थिक हालत में, कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। आरक्षण के बल बूते अपने सामाजिक और आर्थिक हैसियत, मजबूत करने वाले लाभार्थियों को, उन्हीं के वर्ग के लोगों को, वंचितों की चिंता नहीं है। आरक्षण का फायदा उठाकर आगे बढ़ चुका वर्ग, उस पर कुंडली मारे बैठा है। सही मायने में क्रीमी लेयर ही आरक्षण का दोहन कर रही है। जबकि दूसरे आरक्षित सिर्फ उन्हें ताकते रहने को मजबूर है। इस क्रीमी लेयर के खिलाफ बोलने का किसी राजनीतिक दलों में साहस मौजूद नहीं है।

देश में आज भी एक ऐसा बड़ा तबका मौजूद है, जिसके पास आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कारण साफ है कि आरक्षण का लाभ लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके लाभार्थियों से उनका मुकाबला कमजोर पर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि आरक्षण से सरकारी नौकरी में, गिनती के लोगों को ही लाभ मिलने के अलावा, आरक्षण वर्ग की स्थिति में, खास बदलाव नहीं हुआ है।

देश में, दलित और आदिवासी इलाका आज भी, आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल जैसी सुविधाएं उनके क्षेत्रों में आसानी से मयस्सर नहीं होता है। सरकार ने आरक्षण देकर यह मान लिया है कि अब इन वर्गों का विकास अपने आप हो जायेगा। ये देश और समाज की मुख्यधारा में आ जाएंगे। इनके लिए अलग से विकास के प्रयास नहीं किये गये है। यही वजह है कि दलित और जनजातीय समुदाय अभी तक कई कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों से मुक्त नहीं हो सका है। इतना ही नहीं आरक्षण का लाभ ले कर सत्ता का स्वाद चखने वाले नेताओं को भी इसकी चिंता नहीं है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरक्षण की एक नई कैटेगरी (ईडब्ल्यूएस) से किसका भला होगा? आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने का साफ संदेश यही है कि सरकार आर्थिक विषमता की खाई पाटने में नाकाम रही है। गरीबी हटाने की बात सिर्फ चुनावी वादा बन कर रह गई है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी बेरोजगार है। सरकारी नौकरी का आलम यह है कि सरकारी खर्चों के नाम पर सरकारें कम से कम भर्ती करने पर जोड़ दे रही है। सेना में स्थाई तौर पर भर्ती किए जाने की बजाय अग्निवीर योजना को लांच करना इसका प्रमाण है। आर्थिक आरक्षण के खिलाफ तमिलनाडू की डीएमके सरकार ने विरोध जताया है। इसमें डीएमके के अपने राजनीतिक निहितार्थ है। डीएमके का, आरक्षण का यह मसला भी, हिन्दी भाषा के विरोध की तरह है। जिससे सीधा वोट बैंक प्रभावित होता है। यह अलग बात है कि देश के दूसरे नेताओं की तरह, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी ने, कभी आरक्षण में, कभी क्रीमी लेयर का, कभी विरोध नहीं किया। हालांकि अदालत की इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने अदालत को जातिवादी तक करार देते हुए इसे आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश करार दिया है। इसका भी कारण है, दलितों में अपनी छवि, हितैषी की बनाए रखना, अन्यथा कांग्रेस ने आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण का अन्य दलों की तरह ही समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अलग-अलग जजों ने अपनी-अपनी राय रखी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल रहे, लेकिन ये अब तक जारी है। समस्या का सही हल यही है कि उन चीजों को खत्म किया जाए जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है।

हनुमान जी, भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा-आराधना से नववर्ष में दूर होगा ग्रह गोचर

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

मनुष्य के जीवन में 12 राशियों का बहुत महत्व होता है। ये राशि होते है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। 01 जनवरी, 2023 को धनु राशि में सूर्य और बुध ग्रह की युति से बुधादित्य योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ और विशेष फलदायी योग बताया गया है। उसी प्रकार शनिदेव और गुरु बृहस्पति अपनी ही घर में यानि अपनी ही राशि में रहेंगे इसलिए इसे शुभ माना जा रहा है। शनिदेव मकर राशि के स्वामी है और गुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है।मान्यता है कि जब कोई ग्रह अपने घर या राशि में रहता है तो शुभ फल देता है। वहीं चंद्रमा का गोचर मेष राशि में हो रहा है, जहां पाप ग्रह राहु पहले से विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में राहु के साथ चंद्रमा की युति ग्रहण योग बनाती है जिसे शुभ योग नहीं माना जाता है। नववर्ष में धनु राशि में सूर्य और बुध, मकर राशि में शुक्र और शनि, मीन राशि में गुरु बृहस्पति, मेष राशि में चंद्रमा और राहु तथा तुला राशि में केतु ग्रह गोचर रहेगा। भविष्यवक्ता और कुंडली विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा, भगवान शिव की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र और माता दुर्गा की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए।

वहीं हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग की भी पूजा-आराधना करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, शैल मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैजनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ और घुश्मेश्वर है।

राशि के अनुसार

मेष राशि वाले लोग यदि पंचामृत से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करते है तो उन्हें चंद्रमा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी स्थापना चन्द्र देव ने किया था।

वृषभ राशि वाले लोग को शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी तट पर श्रीशैलम नामक पर्वत पर। स्थित है।

मिथुन राशि वाले लोग को महाकालेश्वर (महाकाल) ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए ह्रूँ नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मिथुन राशि वाले लोगों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। महाकालेश्वर (महाकाल) ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है।

कर्क राशि वालों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा एवं ध्यान करना चाहिए। इससे उन्हें अच्छा फल की प्राप्ति होगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित है।

सिंह राशि वालों को बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए । इनकी पूजा करने से सिंह राशि वालों को कारोबार, परिवार, राजनीति, एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त ज्योतिर्लिंग में नौवें स्थान प्राप्त है और यह बिहार (अब झारखंड) के देवघर में स्थित है।

कन्या राशि वालों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को दूध और घी से शिवलिंग को स्नान कराते हुए पूजा करनी चाहिए। इससे भीमाशंकर प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बनाये रखते है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्रि नामक पर्वत पर स्थित है।

तुला राशि वालों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामपुर नामक स्थान पर स्थित है।

वृश्चिक राशि वालों को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से शुभ फल मिलता है। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है।

धनु राशि वालों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजा, जप, तप करना चाहिए। इस पूजा से उन्हें फल की प्राप्ति होगी। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित है।

कुंभ राशि वालों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पंचामृत से स्नान कराकर कमल फूल और धतूरा से पूजा करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है।

मीन राशि वालों को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है।

राहुल गांधी की अंग्रेजी-भक्ति ?

राजस्थान में राहुल गांधी ने अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की जमकर वकालत कर दी। राहुल ने कहा कि भाजपा अंग्रेजी की पढ़ाई का इसलिए विरोध करती है कि वह देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के बच्चों का भला नहीं चाहती है। भाजपा के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं? राहुल ने जो आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाया, वह ज्यादातर सही ही है लेकिन राहुल जरा खुद बताए कि वह खुद और उसकी बहन क्या हिंदी माध्यम की पाठशाला में पढ़े हैं? देश के सारे नेता या भद्रलोक के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इसीलिए भेजते हैं कि भारत दिमागी तौर पर अभी भी गुलाम है। उसकी सभी ऊँची नौकरियां अंग्रेजी माध्यम से मिलती हैं। उसके कानून अंग्रेजी में बनते हैं। उसकी सरकारें और अदालतें अंग्रेजी में चलती हैं। भाजपा ने अपनी नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को स्वभाषा के माध्यम से चलाने का आग्रह किया है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस, दोनों की कई प्रांतीय सरकारें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रोत्साहित कर रही हैं। किसी विदेशी भाषा को पढ़ना एक बात है और उसको अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। मैंने पहली कक्षा से अपनी अंतरराष्ट्रीय पीएच.डी. तक की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से दी है। स्वभाषा के माध्यम से पढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप विदेशी भाषाओं का बहिष्कार कर दें। मैंने हिंदी के अलावा संस्कृत, जर्मन, रूसी और फारसी भाषाएं भी सीखीं। अंग्रेजी तो हम पर थोप ही दी जाती है। राहुल का यह तर्क सही है कि गरीब और ग्रामीण वर्ग के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ते, इसलिए वे पिछड़ जाते हैं। वे भी अंग्रेजी पढ़ें और अमेरिका जाकर अमेरिकियों को भी मात करें। राहुल की यह बात मुझे बहुत पसंद आई लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे कितनी विद्यार्थी अमेरिका या विदेश जाते हैं? कुछ हजार छात्रों की वजह से करोड़ों छात्रों का दम क्यों घोटा जाए? जिन्हें विदेश जाना हो, वे साल-दो साल में उस देश की भाषा जरूर सीख लें लेकिन किसी विदेशी भाषा को 16 साल तक अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाए रखना और उसे करोड़ों बच्चों पर थोप देना कौनसी अक्लमंदी है? हिरण पर घांस क्यों लादी जाए? यदि हमारे नेता लोग चाहते हैं कि गरीबों, ग्रामीणों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों के बच्चों को भी जीवन में समान अवसर मिलें तो देश में सभी बच्चों के लिए स्वभाषा-माध्यम की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए। विदेशी संपर्कों के लिए हमें सिर्फ अंग्रेजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विदेश-व्यापार, विदेश नीति और उच्च-शोध के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ फ्रांसीसी, जर्मन, चीनी, रूसी, अरबी, हिस्पानी, जापानी आदि कई विदेशी भाषाओं की पढ़ाई भी भारत में सुलभ होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है।

किसी विदेशी भाषा को पढ़ना एक बात है और उसको अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। मैंने पहली कक्षा से अपनी अंतरराष्ट्रीय पीएच.डी. तक की परीक्षाएं हिंदी माध्यम से दी है। स्वभाषा के माध्यम से पढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप विदेशी भाषाओं का बहिष्कार कर दें। मैंने हिंदी के अलावा संस्कृत, जर्मन, रूसी और फारसी भाषाएं भी सीखीं। अंग्रेजी तो हम पर थोप ही दी जाती है। राहुल का यह तर्क सही है कि गरीब और ग्रामीण वर्ग के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ते, इसलिए वे पिछड़ जाते हैं। वे भी अंग्रेजी पढ़ें और अमेरिका जाकर अमेरिकियों को भी मात करें। राहुल की यह बात मुझे बहुत पसंद आई लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे कितनी विद्यार्थी अमेरिका या विदेश जाते हैं? कुछ हजार छात्रों की वजह से करोड़ों छात्रों का दम क्यों घोटा जाए? जिन्हें विदेश जाना हो, वे साल-दो साल में उस देश की भाषा जरूर सीख लें लेकिन किसी विदेशी भाषा को 16 साल तक अपनी पढ़ाई का माध्यम बनाए रखना और उसे करोड़ों बच्चों पर थोप देना कौनसी अक्लमंदी है?

फिर कोरोना की दस्तक कोई चूक न हो

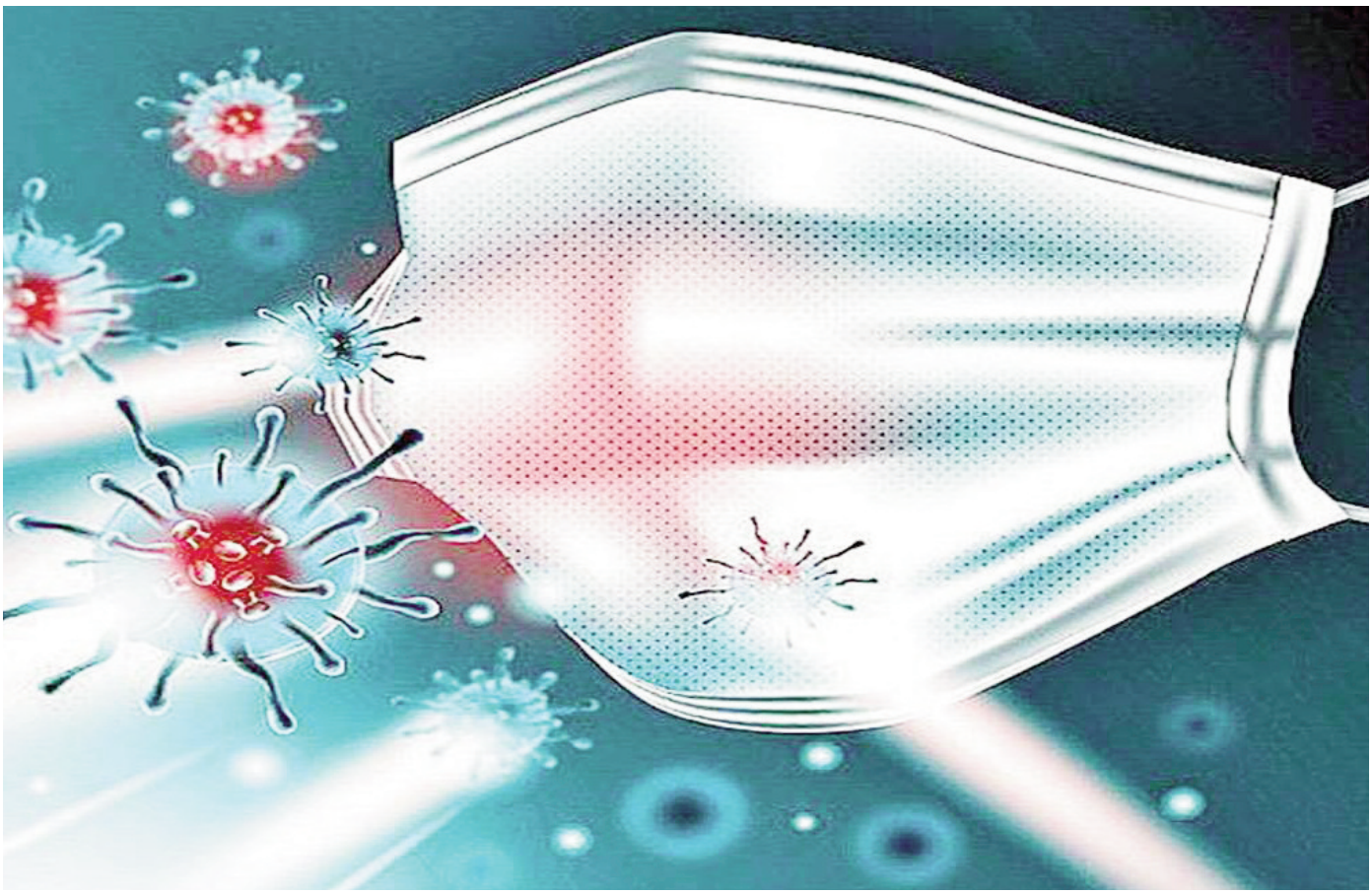

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना के नये वेरिएंट के मामलों और उससे हुई मौतों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में भी चीन में तबाही लाने वाले एवं भयंकर तबाही की आहट देने वाले बेरिएंट बीएफ. 7 के 4 नये मामले मिले हैं, जो गहरी चिन्ता बढ़ा रहे हैं। सरकार सर्तक हो गयी है, आम जनता को भी सावधान रहना होगा। मास्क पहनने एवं बूस्टर डोज लगवाने के अभियान को गति देनी होगी। सार्वजनिक भीड़ को कम करना होगा, सभाओं, त्यौहारों, राजनीतिक आयोजनों पर नियंत्रण करना होगा, स्कूलों को भी सावधान एवं चौकना रहना होना होगा। जरूरत पड़े तो लॉकडाउन भी लगाया जाये। सब जानते हैं कि इस विषाणु और उसके संक्रमण से उपजी बीमारी की शुरूआत चीन से हुई थी और उसके बाद दुनिया का अनुभव बेहद त्रासद, डरावना एवं विस्फोटक रहा। यही वजह है कि अब एक बार फिर चीन में जब कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ने की खबरें आ रही हैं तब दुनिया के अनेक देशों के साथ-साथ भारत में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। खबरों के मुताबिक चीन में स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है।

कोरोना की नयी लहर लाने वाले वाले वेरिएंट बीएफ.7 एक बार फिर बड़े महासंकट का इशारा कर रही है। चीन एवं दुनिया के अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता में डालने लगे हैं, क्योंकि कोरोना की पूर्व लहरों में भारी जन-तबाही हुई है। अब इस नयी लहर को लेकर जैसे भयावह दृश्य चीन में बने हैं, वे एक भय, डर एवं आशंका का माहौल बना रहे हैं, भारत के लिये सुरक्षित जीवन के लिये बूस्टर डोज एक जरूरी एवं उपयोगी कदम है। पिछले लम्बे समय से कोरोना महामारी को लेकर राहत का माहौल हमने देखा था, उससे यह लगने लगा था कि अब शायद दुनिया पहले की तरह सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है। लेकिन अब फिर चीन से जैसी खबरें आ रही हैं, वह एक तरह से सतर्क रहने की चेतावनी दे रही हैं, ताकि समय रहते कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। भारत ने पूर्व में कोरोना महामारी को परास्त करने में जो उपक्रम किये, वैसे ही उपक्रम किये जाने की जरूरत है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार अगर सतर्क हुई है तो यह उसकी जनता के प्रति जागरूकता को दशार्ता है, जो आवश्यक भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को एक बैठक करके हालात की समीक्षा की। उसके बाद नीति आयोग की तरफ से लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह में मास्क लगाने की सलाह दी गई। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि कोरोना के हर पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। इससे इस बात पर नजर बनी रहेगी कि देश में इस वायरस का कोई नया वेरिएंट

तो नहीं आ गया। ये सावधानियां किसी भयंकर विनाश से भारत की जनता को बचाने एवं सुरक्षित करने के लिये जरूरी है।

भारत में अभी बेवजह की चिन्ता एवं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो यहां नए केसों की संख्या सबसे निचले स्तर पर है। दूसरे, देश में आबादी के बड़े हिस्से को टीका लग चुका है। साथ ही, यहां नैचरल इम्यूनिटी भी विकसित हो चुकी है। दरअसल, भारत में कोरोना से बचाव के लिए जिस तरह व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया और लोगों ने इस मसले पर जागरूकता दिखाई, वह यहां राहत का एक बड़ा कारण है। माना जा रहा है कि टीकाकरण के मामले में भारत को जैसी उपलब्धि मिली है, उसमें अब कोरोना के बहुरूपों के संक्रमण से लोग बचे रहेंगे। टीका बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ सरकार की ओर से भी इस बात का आश्वासन दिया गया था कि टीका कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा दीवार के तौर पर काम करेगा। इसके बावजूद विषाणुओं की प्रकृति को देखते हुए हर स्तर पर सजग रहने एवं बूस्टर डोज को प्राथमिकता देने की जरूरत है, अन्यथा इसकी मार से उपजी त्रासदी दुनिया देख चुकी है।

कोरोना का अब तक का अनुभव बताता है कि इस वायरस को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लेना चाहिए। यह एक बार फैल गया तो इस पर नियंत्रण आसान नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जैसे भी हो इसे फैलने से ही रोका जाए। पहले दौर में जब वुहान से विषाणु के संक्रमण की खबरें आई थी, तब शायद वक्त पर अपने-अपने देशों में सावधानी बरतने को लेकर उतनी जागरूकता नहीं आ पाई थी, नियंत्रण के साधन नहीं है, आम जनता एवं सरकारों तैयार भी नहीं थी। इसलिए उसका असर भी व्यापक हुआ और समूची दुनिया इसकी चपेट में आए। भारत उससे सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में से एक था। इसलिए स्वाभाविक ही इस बार चीन में कोरोना से स्थिति बिगड़ने की खबरें आने के साथ ही भारत में सावधानी बरतने को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने लगे हैं। यह सरकार की सूझबूझ भी है और जागरूकता भी है।

विदेशों में कोरोना के नए मामलों में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी सचमुच चिंताजनक है। खासकर चीन में तो भयावह हालात हैं। जिस व्यापक स्तर पर उसके फैलने एवं जिस बड़े पैमाने पर मौतों की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, वह भारत सहित समूची दुनिया को सर्तक एवं सावधान हो जाने की टंकार है। उसे समय पर गंभीरता से लेना महामारी के प्रकोप को कम करना ही माना जायेगा। चीन की दृश्य डरावने एवं चिन्ता पैदा करने वाले हैं, वहां अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, शवदाह गृहों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सही सूचनाएं सामने नहीं आ रहीं। मंगलवार को चीनी सरकार ने कहा कि किसी मौत को कोविड-19 से हुई मौत माना जाए या नहीं, यह तय करने के आधारों में बदलाव किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन वास्तविक तथ्यों से दुनिया को अंधेरे में रखना चाहती है, मौतों की वास्तविक संख्या छुपाना चाहती है। अगर यह सच है तो इससे चीन में हुए कोरोना विस्फोट की वास्तविक प्रकृति को समझने में दिक्कत होगी। जाहिर है, ऐसे में किसी नए

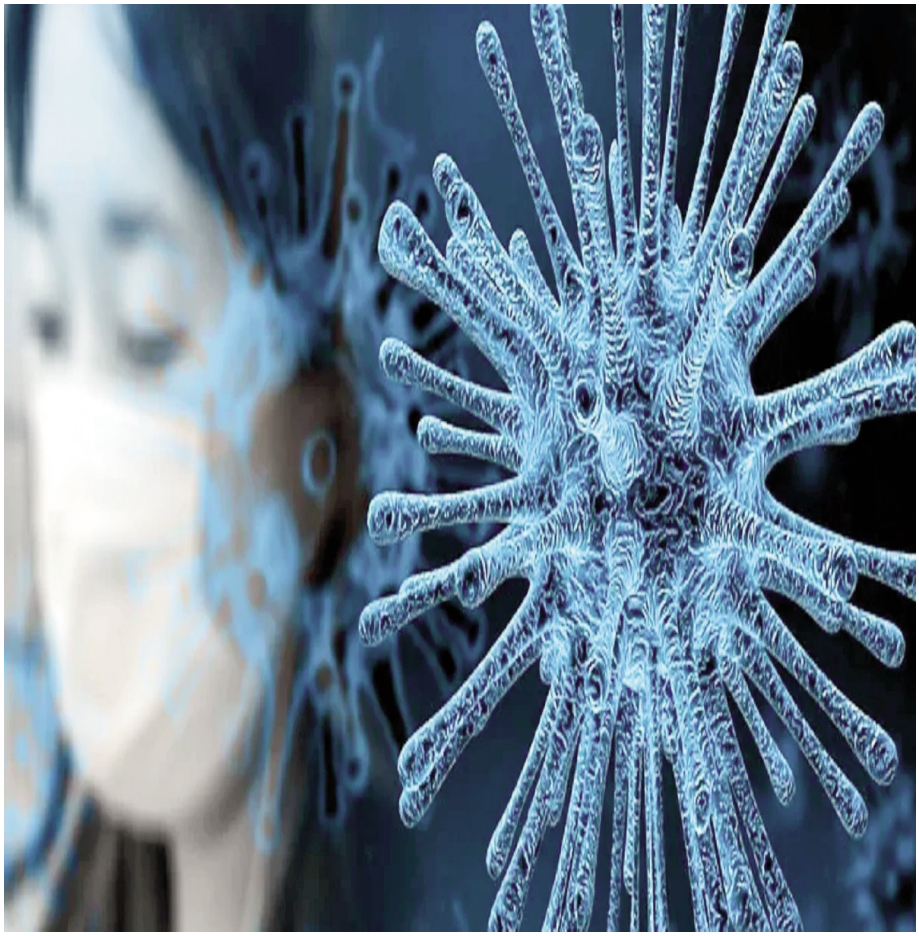

कोरोना का अब तक का अनुभव बताता है कि इस वायरस को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लेना चाहिए। यह एक बार फैल गया तो इस पर नियंत्रण आसान नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि जैसे भी हो इसे फैलने से ही रोका जाए। पहले दौर में जब वुहान से विषाणु के संक्रमण की खबरें आई थी, तब शायद वक्त पर अपने-अपने देशों में सावधानी बरतने को लेकर उतनी जागरूकता नहीं आ पाई थी, नियंत्रण के साधन नहीं है, आम जनता एवं सरकारों तैयार भी नहीं थी। इसलिए उसका असर भी व्यापक हुआ और समूची दुनिया इसकी चपेट में आए। भारत उससे सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में से एक था।

वेरिएंट के रूप में दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की नई लहर फैल जाने की आशंका और मजबूत होती है और उससे समाधान पाने की राह उतनी ही जटिल होगी।

भारत में कठिन कोरोना परिस्थितियों में भी देशवासियों ने जिस तरह से कोरोना की पूर्व लहरों का सामना किया है वे आज भी नयी लहर का सामना करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सतत जागरूकता, देशवासियों और कोरोना वारियर्स के लगातार संघर्ष ने हताशा के बीच भी जीवन को आनंदित बनाने का साहस प्रदान किया है, जो समूची दुनिया के लिये प्रेरणा का माध्यम बना है। इस समय दुनिया के अनेक देश कोरोना के नए वैरियंट बीएफ.7 से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना के नए केस आये हैं लेकिन भारतीयों के चेहरे पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। इसका श्रेय देश में सफलतापूर्वक चले टीकाकरण अभियान को जाता है। लेकिन जानबूझकर लापरवाही एवं सरकारी हिदायतों की उपेक्षा घातक हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत दुनिया में सबसे तेज कोरोना टीकाकरण करने वाला देश है। एक बार फिर कोविड-19 के दस्तक के समय दी गयी हिदायतों को दोहराने की जरूरत है कि किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। साबुन से 30 सेकंड तक हाथ धोए। हमें पूरे दिन साफ और शुद्ध पानी पीना चाहिये, हमें बाहर के खाने से बचना चाहिये, साथ ही ज्यादा मसालेदार और तैयार पेय पदार्थों से परहेज करना चाहिये। सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। बेवजह भीड़ का हिस्सा न बने। इस प्रकार हम खुद को स्वच्छ एवं सावधान रखते हुए नये बेरिएंट बीएफ.7 के खौफ एवं नुकसान से स्वयं को बचा सकेंगे। हमें नयी लहर का मुकाबला सामूहिक इच्छाशक्ति, संकल्प एवं जिम्मेदारी से करना होगा। अगर हम ऐसा कर गए तो कोरोना का नया वायरस बेरिएंट बीएफ.7 भी पराजित हो जाएगा। इसलिए हिम्मत से काम लेना होगा।

सर्दियों में बारिश के अभाव ने बढ़ाया प्रदूषण स्तर

सर्दियों की आमद ने एक बार फिर गंगा के मैदानी इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को ह्यखराबह्न और ह्यगंभीरह्न श्रेणियों के बीच ला खड़ा कर दिया है। बात की गंभीरता इसिस से पता चलती है कि दिल्ली-एनसीआर में दिसंबर के पहले पखवाड़े के सबसे तेज धूप और खुले आसमान वाले दिनों पर भी वायु गुणवत्ता ह्यखराबह्न की श्रेणी में ही रही।

अब चूंकि रबी की फसल की बुवाई के बाद पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में पराली जलाना कम हो गया है, बढ़ते वायु प्रदूषण की ज़िम्मेदारी औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन, क्षेत्रीय प्रदूषण पर है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि प्रदूषण के फैलाव को रोकने के लिए, शहरों को सभी क्षेत्रों में और स्रोत पर उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि बारिश के रूप में मौसम की स्थिति कुछ तात्कालिक राहत लाएगी लेकिन बढ़ते जलवायु परिवर्तन के साथ ये भी असंगत हो गई हैं।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश का पूर्ण अभाव रहा है। इसके मद्देनजर, इस क्षेत्र में एक स्थिर हवा का पैटर्न देखा जा सकता है और उसकी गति भी बहुत धीमी है। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस-10 डिग्री सेल्सियस की सीमा में टिका हुआ है। जैसे-जैसे तापमान में गिरावट आती है, नमी की मात्रा बढ़ने के कारण ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएँ भारी हो जाती हैं। इससे पृथ्वी की सतह के करीब प्रदूषकों को बांध रखने के लिए हवाओं की क्षमता भी बढ़ जाती है।

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्काईमेट वेदर में मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा, ह्लमैदानी इलाकों में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के पहुंचने के साथ, न्यूनतम तापमान अब गिर जाएगा और इकाई में स्थिर हो जाएगा। इससे वातावरण से प्रदूषकों को दूर करना बहुत मुश्किल होगा। न्यूनतम तापमान जितना अधिक गिरेगा, पृथ्वी के करीब की गैसों की परत उतनी ही मोटी होगी। और यह परत जितनी मोटी होगी, सूरज की किरणों या हवाओं के लिए इस परत के माध्यम से प्रवेश करना और प्रदूषण को बहा ले जान अधिक कठिन होगा।ह्व

सर्दियों के दौरान, वायुमंडल का सबसे निचले भाग में हवा की परत पतली होती है क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास ठंडी हवा सघन होती है। ठंडी हवा ऊपर की गर्म हवा के नीचे फंसी रहती है जो एक प्रकार का वायुमंडलीय ह्यढक्कनह्न बनाती है। इस घटना को कहा जाता है विंटर इनवर्ज़्न । चूँकि हवा का मिश्रण केवल इसी परत के भीतर होता है, इसलिए हवा के प्रदूषकों के

पास वातावरण में फैलने के लिए इस मौसम में पर्याप्त जगह नहीं होती।

आमतौर पर साल के इस समय तक, क्षेत्र में सर्दियों की बारिश और बर्फबारी के कम से कम एक या दो दौर देखे जाते हैं। हालांकि, हिमालय में किसी भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) की अनुपस्थिति के कारण, बारिश पूरे मैदानी इलाकों से बच रही है। हालांकि, बीच-बीच में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आते रहे हैं, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि को शुरू करने में सक्षम नहीं थे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, नवंबर में पूरे उत्तर भारत में पांच पश्चिमी विक्षोभ गुजरे। इनमें से दो डब्ल्यूडी (नवंबर 2-5 और 6-9) के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट बारिश या बर्फबारी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई। शेष तीन कमजोर (13-15 नवंबर, 18-21 और 22-24 नवंबर) 30 डिग्री एन के उत्तर में स्थित थे और इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते थे।

पश्चिमी विक्षोभ पूरे वर्ष पश्चिमी हिमालय के मौसम को प्रभावित करता रहता है। हालांकि, नवंबर तक ही पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और आवृत्ति धीरे-धीरे गति पकड़ने लगती है। वे पहाड़ी राज्यों के बहुत करीब से निचले अक्षांशों में भी यात्रा करना शुरू कर देते हैं, जिससे मौसम की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। जनवरी और फरवरी तक तीव्रता और आवृत्ति चरम पर होती है। आईएमडी के एक अध्ययन के अनुसार , नवंबर और दिसंबर के महीनों के दौरान औसतन 2 मध्यम से गंभीर डब्ल्यूडी के मामले देखे गए और 3 मामले क्रमशः जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान देखे गए।

हऊउत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है, खासकर सर्दियों के दौरान। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से पहाड़ी राज्यों

और भारत-गंगा के मैदानों (क्ष्ह्र) में बारिश और बर्फबारी होती है। यह इस सक्रिय प्रणाली के पारित होने के बाद ही है, जो सर्दियों के मौसम की शुरूआत की घोषणा करते हुए मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं को धकेलती है।

इस मौसम में अब तक पैटर्न गायब होने के कारण, मौसम की गतिविधि या हवा के पैटर्न में बदलाव (हवा की गति में वृद्धि) के कारण वातावरण में प्रदूषक साफ नहीं हो पा रहे हैं। सर्दियों के वायु प्रदूषण के केंद्र आईजीपी में भी हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं क्योंकि मौसम विज्ञानियों ने दिसंबर के बाकी दिनों में कम बारिश की भविष्यवाणी की है।

ह्लयह केवल भारत-गंगा के मैदानों के बारे में नहीं है, बल्कि देश के अधिकांश हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ती हुई देखी गई है। पीएम 10 इसमें अकेला योगदानकर्ता नहीं था बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर भी उच्च था। इससे पता चलता है कि सिर्फ निर्माण गतिविधियां नहीं थीं बल्कि जलने की घटनाएँ भी अधिक हुईं। इसके अलावा, ला नीना जैसी बड़े पैमाने की मौसम संबंधी घटनाएं भी परिसंचरण को धीमा करने में योगदान दे रही हैं। हमें वायु गुणवत्ता की भविष्यवाणी करने के लिए और अधिक ह्यपूर्व चेतावनी प्रणालीह्ल की आवश्यकता है। ये प्रणालियां हमें बता सकती हैं कि मंद मौसम प्रणालियों का सापेक्षिक योगदान क्या है ,ह्व आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एसएन त्रिपाठी ने कहा।

भारत-गंगा के मैदानी इलाकों के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर परिलक्षित हो रहा है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2022 में, राजधानी दिल्ली में पीएम 2.5 की सघनता 183.38 ४/3 थी, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दैनिक सुरक्षित सीमा 60 ४/3 से तीन गुना अधिक है। इसी तरह, गाजियाबाद, कानपुर, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे अन्य शहरों में पीएम 2.5 का स्तर सुरक्षा सीमा से लगभग दोगुना दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान के चलते, 2022 में पीएम 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक था लेकिन 2021 की तुलना में कम था।

इस वर्ष बारिश की कमी के बावजूद नवंबर 2022 में पीएम 2.5 का स्तर 2021 की तुलना में कम था। जबकि मॉनसून की देरी से वापसी के कारण अक्टूबर दोनों वर्षों के लिए वर्षा अधिशेष था, यह हवा के पैटर्न और ला नीना थे जो प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदूषण के स्तर को अलग-अलग परिभाषित करते थे।

विलंबित मानसून ने 2021 और 2022 दोनों के लिए खरीफ फसल की कटाई और पराली जलाने की घटनाओं को नवंबर तक बढ़ा दिया। हालांकि, इसके बाद मौसम विज्ञान ने दो वर्षों में अलग-अलग भूमिका निभाई।

2021 में, सक्रिय ला नीना स्थितियों के कारण सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पारित होने से उत्तर पश्चिम भारत में नियमित अंतराल पर बारिश और हिमपात के कुछ अच्छे दौर आए। इसने प्रदूषकों को थोड़े समय के लिए धो दिया लेकिन सर्दियों की बारिश ने भी तापमान को कम रखा और आर्द्रता के स्तर में वृद्धि की। इस प्रकार, प्रदूषक लंबे समय तक वातावरण में फंसे रहे, जिसके परिणामस्वरूप स्मॉग बना। इसके अलावा, हवा

आमतौर पर साल के इस समय तक, क्षेत्र में सर्दियों की बारिश और बर्फबारी के कम से कम एक या दो दौर देखे जाते हैं। हालांकि, हिमालय में किसी भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (डब्ल्यूडी) की अनुपस्थिति के कारण, बारिश पूरे मैदानी इलाकों से बच रही है। हालांकि, बीच-बीच में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आते रहे हैं, लेकिन वे किसी भी महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि को शुरू करने में सक्षम नहीं थे।भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, नवंबर में पूरे उत्तर भारत में पांच पश्चिमी विक्षोभ गुजरे। इनमें से दो डब्ल्यूडी (नवंबर 2-5 और 6-9) के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट बारिश या बर्फबारी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई।

का पैटर्न भी उत्तर-पश्चिमी दिशा से था, जिसका मतलब था कि हरियाणा में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषकों को शहरों में ले जाया गया था। इन सभी ने सामूहिक रूप से 2021 में मैदानी इलाकों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया।

इस बीच, 2022 में, भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा से उत्तर-पश्चिमी हवाओं के बजाय राजस्थान से पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं। यह किसी भी मौसम प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण था जो हवा के पैटर्न को बदल सकता था। इसलिए, पराली जलाने से प्रदूषकों को ले जाने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में पिछले साल जितनी नहीं पहुंच सकीं। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (क्अपफ्क्) के अनुसार 2022 में पंजाब और हरियाणा राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं 2021 की तुलना में 30% (78,291 से 53,583) तक कम थीं । इसके अलावा, सर्दियों की बारिश भी अब तक कम रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान औसत से ऊपर रहा है। इस वजह से नमी का स्तर बहुत कम नहीं था, जो वातावरण में प्रदूषकों को फंसाने में सक्षम नहीं थे। हालाँकि, जैसे-जैसे तापमान में गिरावट आती है और बारिश इस क्षेत्र में मायावी बनी रहती है, वर्तमान में हवा में निलंबित प्रदूषकों के जल्द ही किसी भी समय धुल जाने की संभावना कम है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा, ह्लयह स्पष्ट है कि बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए स्रोत पर प्रदूषकों को कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मौसम विज्ञान भी वायु गुणवत्ता स्तरों में एक जटिल भूमिका निभाता है। फिलहाल यह देखकर खुशी हो रही है कि नवंबर 2022 में गंगा के मैदानों के कुछ शहरों में वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत बेहतर था, मगर फिर भीयह सीपीसीबी के सुरक्षा स्तरों की तुलना में बहुत अधिक है, जो वैसे भी डब्ल्यूएचओ के कड़े वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों की तुलना में अधिक लचीले हैं।

बहुआयामी गरीबी और शोषण में जी रहे बच्चे

नांदेड़, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है. यह क्षेत्र गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और अपने सिख गुरुद्वारों के लिए प्रसिद्ध है. यह मराठवाड़ा मंडल के तहत महाराष्ट्र के 36 जिलों में से एक है और इसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा जाता है. भौगोलिक रूप से, यह क्षेत्र ज्यादातर सूखाग्रस्त है. नांदेड़ में कृषि मुख्य व्यवसाय है और यहां के आम लोग ज्यादातर मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं. कम वर्षा के कारण अधिकांश मजदूर काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और कई दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं. यहां की 86 प्रतिशत महिलाएं गैर-कृषि व्यवसायों से जुड़ी हैं. ईंट भट्ठों में काम करने के अलावा लोग अपने परिवारों के साथ गन्ने के खेतों में भी मजदूरी करते हैं. कुछ लोग मुंबई और पुणे की कंपनियों में काम करने जाते हैं. यहां के लोग अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में पलायन करते रहते हैं. कुछ महिलाएं गृहिणी के रूप में काम करती हैं, जबकि कुछ पुरुष कपड़ों की दुकानों में सहायक और विक्रेता के रूप में काम करते हैं.

नांदेड़ के अलग-अलग इलाकों में कपड़े का कारोबार अच्छा चल रहा है. शहर में अच्छी कपड़े की दुकानें होने के कारण जिले भर के गांवों और कस्बों से अच्छे ग्राहक यहां आते रहते हैं. नांदेड़ में वजीराबाद, श्रीनगर, जूना मोंढा और चौक अपनी कपड़े की दुकानों के लिए जाने जाते हैं. इन जगहों के आसपास दलित बस्ती है. इन दुकानों में काम करने वाले ज्यादातर लोग इन्हीं बस्तियों से आते हैं. शहरी आवास योजना के तहत कुछ लोगों को पक्के मकान मिल गए हैं, लेकिन यहां के ज्यादातर लोग पीढ़ियों से एक या दो कमरे के किराए के मकान में रह रहे हैं. यहां सरकारी नल से पानी की आपूर्ति की जाती है. शहर के लोग आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए जंगबरी, शिवाजी चौक, श्याम नगर और शिवाजी नगर के सरकारी अस्पतालों में जाते हैं. यहां का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल विष्णुपुरी में है लेकिन स्कूल की बात करें तो इस क्षेत्र के आसपास बहुत कम सरकारी स्कूल हैं. ज्यादातर बच्चे मजदूर हैं. इसके पीछे गरीबी एक बड़ा कारण है. पिछड़े वर्ग के अधिकांश बच्चे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं.

नतीजतन, बाल श्रम का आंकड़ा बढ़ा है क्योंकि बाल श्रम वयस्क श्रम से सस्ता है इसलिए, नियोक्ता बच्चों से काम करवाना पसंद करते हैं. दलित और आदिवासी बच्चों के साथ जाति-आधारित भेदभाव उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार से जुड़ा है. इन बच्चों को कई स्तर पर शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें उच्च ड्रॉपआउट दर, निम्न पारिवारिक साक्षरता दर, सरकारी स्कूलों में खराब शैक्षिक मानक, स्कूलों में भेदभाव और बहिष्करण प्रथाएं आदि शामिल हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक बाल श्रम दर वाले राज्य हैं. इस क्षेत्र की निवासी सीमा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे गरीबी शिक्षा में बाधाएं पैदा करती हैं. वह कहती है कि उसके माता-पिता उसे स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और अच्छी स्टेशनरी जैसी अच्छी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण उसे अक्सर उसके साथियों द्वारा चिढ़ाया जाता था. यह उसे अपमानजनक लगता था. दूसरी ओर उच्च फीस के कारण माता-पिता उसकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते थे और इसलिए वे अपनी बेटियों को शिक्षित करने में कम रुचि रखते थे. मजबूरन उसे स्कूल जाना बंद करना पड़ा.

शैक्षिक सुविधाओं की कमी, वंचित छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता की कमी (चाहे वह पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति या स्कूल का माहौल हो), कम पारिवारिक साक्षरता और शिक्षा नीति के अधिकार के कार्यान्वयन की कमी आदि मुख्य कारण हैं जो गरीब बस्ती के बच्चों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 79 प्रतिशत बच्चे 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच स्कूल छोड़ देते हैं. जबकि शिक्षा का अधिकार नीति में जाति

या वर्ग के बावजूद सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है. लेकिन सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन के लचर तरीका और शिक्षकों द्वारा छात्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देना इसका एक मुख्य कारण है. वहीं छात्रों और शिक्षकों का अनुचित अनुपात भी प्रमुख भूमिका निभाता है. शिक्षा के लिए महाराष्ट्र की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई प्लस) 2018-19 के अनुसार, 4928 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लंघन कर रहे हैं. यह कुल संख्या का 16.30 प्रतिशत है. इसी तरह 3177 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक हैं.

कोमल पंद्रह साल की लड़की है. वह दुकानों में हेल्पर का काम करती है. कोमल और उसके दो भाई-बहनों को अकेले मां ने ही पाला है. गरीबी ने जल्द ही उसे यह अहसास करा दिया था कि उसकी मां अकेले ही घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है. इसलिए उसने अपने परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता अर्जित करने के लिए एक कपड़े की दुकान में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया. आम तौर पर असंगठित क्षेत्रों में लोगों को जल्द नौकरी छूटने का डर होता है, जिसका फायदा दुकान मालिक कमजोर श्रमिकों पर अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए उठाते हैं. महिलाएं और लड़कियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं. अधिकांश युवा लड़कियां बाधाओं को देखते हुए केवल अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए काम करती हैं, इसलिए वे अपनी नौकरी आसानी से नहीं छोड़ सकतीं. वह इसी परिस्थिति में स्वयं को ढ़ालने का प्रयास करती हैं. उन्हें अपनी नौकरी खोने की चिंता होती है क्योंकि वह यह भी जानती हैं कि पूरा बाजार ऐसा ही है और हर जगह शोषण आम है. हालांकि जब शोषण अत्यधिक हो जाता है, तो कई लड़कियों को काम छोड़कर घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. कोमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आखिरकार उसने भी नौकरी छोड़ दी. भारत सरकार ने मार्च 2020 में अचानक लॉकडाउन की घोषणा की. जिससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें कई तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ा. लोग मीलों पैदल चलने को मजबूर हुए. उन्हें अपने मूल राज्य और गांव तक पहुंचने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की पैदल यात्रा करनी पड़ी थी. कपड़ा बाजार भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ था और दुकानों तथा मॉल के कर्मचारियों को विस्थापित होना पड़ा था. लॉकडाउन के दौरान कपड़ा बाजार में काम करने वाले बाल मजदूरों को अपने मालिकों से कोई मदद नहीं मिली थी. पूजा, जो एक नाबालिग लड़की है और अपना घर चलाने के लिए काम करती है, लॉकडाउन के दौरान अपना घर चलाने के लिए वह अपने मालिक से राशन और कुछ पैसे पाने की उम्मीद कर रही थी लेकिन उसे इस स्थिति में भी कोई मदद नहीं मिली थी. इसके विपरीत उसे नियोक्ताओं द्वारा बुलाया गया और आधे दिन में ही बहुत काम लिया गया, लेकिन जब भुगतान करने का समय आया, तो उसे बताया गया कि उसे केवल आधा वेतन ही मिलेगा क्योंकि वह आधा दिन काम करती है. बहुआयामी परिस्थिति में बाल श्रम को मजबूर बच्चों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिसे

क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है?

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

आरटीआई अधिनियम, 2005 सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके लोगों को नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। कार्यकताओं, वकीलों, नौकरशाहों, शोधकताओं और पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के नागरिक पंचायत स्तर से लेकर संसद तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अधिकांश आरटीआई आवेदन ऐसे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं जो अपने मूल अधिकारों और अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसने उस हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोगों ने यह जानने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया है कि करदाताओं के पैसे के साथ क्या हो रहा है। इससे उन्हें आदर्श, कॉमनवेल्थ गेम्स और व्यापम जैसे बड़े घोटालों का पदार्फाश करने में मदद मिली है। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 60 लाख आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। इसका उपयोग नागरिकों के साथ-साथ मीडिया द्वारा भी किया जाता है। वे मानवाधिकारों के उल्लंघन का पदार्फाश करने में भी सक्षम रहे हैं, और फिर उन मामलों में भी जवाबदेही तय करने में सक्षम रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का दावा करने का अधिकार है। इससे जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत हुआ।

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। उदा. न्यायपालिका अधिनियम के अधीन नहीं है। आरटीआई के कार्यान्वयन के लिए पीआईओ को आवेदक को फोटो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

इस कानून के बारे में जागरूकता की कमी और व्यापक रूप से अपनाने की कमी आज भी है। 150 शब्दों के भीतर आरटीआई आवेदन वाले कुछ राज्य है वहां विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल सकता है। जन सूचना अधिकारी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते है कि विभाग के पास जानकारी नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना रखने वाले का पता लगाने और आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। बड़ी संख्या में इनकार जहां लोगों को सिर्फ यह बताया जाता है कि यह जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती है, जो एक अवैध इनकार है। सरकार से सूचना मांगने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, डेटासेट और सूचना का रखरखाव सार्वजनिक डोमेन में रखना एक बड़ी समस्या बन गई है। उदाहरणः कोविड -19 के दौरान जब सरकार से पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जान चली गई, प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में, तो सरकार ने कहा, हमारे पास कोई डेटा नहीं है. सूचना आयुक्तों के पास आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। आयोग के आदेश के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यकताओं को मुआवजे के पुरस्कार के मामले में, अनुपालन सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड रखने की खराब प्रथाएं सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे पूरक कानूनों को कमजोर करती है। सरकार द्वारा संशोधन के प्रयास भी इसको कमजोर करते है जैसे फाइल नोटिंग सूचना के अधिकार का हिस्सा नहीं होंगे।

भारत सक्षम है मानव एकता को बल देने में

अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच मानवीय एकता के महत्व को बताने के लिए, गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को विश्व एकजुटता कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो दुनियाभर में गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। इस दिवस को मनाते हुए हर व्यक्ति शिक्षा में योगदान देकर, गरीबों या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दिवस के माध्यम से सरकारों को सतत विकास लक्ष्य के गरीबी और अन्य सामाजिक बाधाओं का जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विविधता में एकता दशार्ने, विभिन्न सरकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों को याद दिलाने, लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को बताने, सतत विकास के लिए लोगों, सरकारों को प्रेरित करने, गरीबी को मिटाने के नए रास्ते खोजने एवं लोगों को गरीबी, भुखमरी, बीमारियों से बाहर निकालने के लिए इस दिवस का विशेष महत्व है। इसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जी-20 देशों के समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत ने संभाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी को संभालने का अर्थ है भारत को सशक्त करने के साथ-साथ दुनिया को मानव एकता की दृष्टि से एक नया चिन्तन, नया आर्थिक धरातल, शांति एवं सह-जीवन की संभावनाओं को बल देना।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ह्लसंयुक्त राष्ट्र के निर्माण ने विश्व के लोगों और राष्ट्रों को एक साथ शांति, मानवाधिकारों और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित किया। संगठन की स्थापना अपने सदस्यों के बीच एकता और सद्भाव के मूल आधार पर की गई थी, जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में व्यक्त की गई थी, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों की एकजुटता पर निर्भर करती है।ह्व अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सतत विकास एवं समतामूलक विकास के एजेंडा पर आधारित है, जो अपने आप में गरीबी, भूख और बीमारी जैसे कई दुर्बल पहलुओं से लोगों को बाहर निकालने के लिए केंद्रित है। ह्यमिलेनियम डिक्लेरेशनह्व को ध्यान में रखते हुए, एकजुटता को 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत मूल्यों में से एक माना जाता है, जिसके तहत

कम से कम लाभ उठाने वाले और सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करने वाले लोग उन लोगों की मदद के योग्य होते हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ मिलता है।

आज समूची दुनिया में मानवीय एकता एवं चेतना के साथ खिलवाड़ करने वाली त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण परिस्थितियां सर्वत्र परिव्याप्त हैं-जिनमें आतंकवाद सबसे प्रमुख है। जातिवाद, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, महंगाई, गरीबी, भिखमंगी, विलासिता, अमीरी, अनुशासनहीनता, पदलिप्सा, महत्वाकांक्षा, उत्पीड़न और चरित्रहीनता आदि अनेक परिस्थितियों से मानवता पीड़ित एवं प्रभावित है। उक्त समस्याएं किसी युग में अलग-अलग समय में प्रभावशाली रहीं होंगी, इस युग में इनका आक्रमण समग्रता से हो रहा है। आक्रमण जब समग्रता से होता है तो उसका समाधान भी समग्रता से ही खोजना पड़ता है। हिंसक परिस्थितियां जिस समय प्रबल हों, अहिंसा का मूल्य स्वयं बढ़ जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि आपको मानवता में विश्वास खोना नहीं चाहिए। मानवता एक महासागर है। यदि महासागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो भी महासागर गंदा नहीं होता है।ह्व ऐसे ही विश्वास को जागृत करने के लिये ही विश्व मानव एकता दिवस की आयोजना की गई है।

गरीबी का कारण हिंसा, आतंक, अप्रामाणिकता, संग्रह, स्वार्थ, शोषण और क्रूरता आदि हैं इनके दंश

मानवता को मूर्च्छित कर रहे हैं एवं मानव एकता की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इस मूर्च्छा को तोड़ने के लिए अहिंसा और सह-अस्तित्व का मूल्य बढ़ाना होगा तथा सहयोग एवं संवेदना की पृष्ठभूमि पर स्वस्थ समाज-संरचना की परिकल्पना को आकार देना होगा। दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता मानव एकता का आधार तत्व है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व की तरह दूसरे के अस्तित्व को अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वह उसके प्रति संवेदनशील नहीं बन पाएगा। जिस देश और संस्कृति में संवेदनशीलता का स्रोत सूख जाता है, वहाँ मानवीय रिश्तों में लिजलिजापन आने लगता है। अपने अंग-प्रत्यंग पर कहीं प्रहार होता है तो आत्मा आहत होती है। किंतु दूसरों के साथ ऐसी घटना घटित होने पर मन का एक कोना भी प्रभावित नहीं होता। यह संवेदनहीनता की निष्पत्ति है। इस संवेदनहीन मन की एक वजह सह-अस्तित्व का अभाव भी है। आज हम इतने संवेदनशून्य हो गये हैं कि औरों का दुःख-दर्द, अभाव, पीड़ा, औरों की आहें हमें कहीं भी पिघलाती नहीं। देश और दुनिया में निर्दोष लोगों की हत्याएं, हिंसक वारदातें, आतंकी हमले, अपहरण, जिन्दा जला देने की रक्तरंजित सूचनाएं, महिलाओं के साथ व्यभिचार-बलात्कार की वारदातें पढ़ते-देखते हैं पर मन इतना आदती बन गया कि यूं लगता है कि यह सब तो रोजमर्रा का काम है। न आंखों में आंसू छलकते हैं, न पीड़ित मानवता के साथ सहानुभूति जुड़ती है। न सहयोग की भावना जागती है और न नृशंस क्रूरता पर खून खौलता हैं। हमें सिर्फ स्वयं को बचाने की चिन्ता है। तभी औरों का शोषण करते हुए नहीं सकुचाते। हमें संवेदना को जगाना होगा। तभी जे.के. राउलिंग ने कहा भी है कि हमें दुनिया को बदलने के लिये जादू की आवश्यकता नहीं है। हम बस मानव की सेवा करके ऐसा आसानी से कर सकते हैं।ह्न इसी मानव-सेवा की मूल भावना मानव एकता दिवस का हार्द है।

सामाजिक मूल्य-परिवर्तन और मानदंडों की प्रस्थापना से लोकचेतना में परिष्कार हो सकता है। इस दृष्टि से विश्व मानव एकता दिवस की उपयोगिता बढ़-चढ़ कर सामने आ रही है। इसलिये ऑड्रे हेपबर्न ने कहा था कि जब तक दुनिया अस्तित्व में है, अन्याय और अत्याचार होते रहेंगे। जो लोग सक्षम और समर्थ हैं, उनकी जिम्मेदारी अधिक है कि वे लोग अपने से निर्बल लोगों को भी स्नेह दें। विश्व मानव एकता दिवस दुनिया भर में मानवीय जरूरतों पर ध्यान आकर्षित करने की मांग करता है और इन जरूरतों को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की आवश्यकता को व्यक्त करता है। हर साल, आपदाओं एवं मानव-भूलों से लाखों लोगों विशेषतः दुनिया के सबसे गरीब, सबसे हाशिए पर आ गये लोग और कमजोर व्यक्तियों को अपार दुःख का सामना करना पड़ता है। मानवतावादी सहायताकर्मी इन आपदा प्रभावित समुदायों एवं लोगों को राष्ट्रीयता, सामाजिक समूह, धर्म, लिंग, जाति या किसी अन्य कारक के आधार पर भेदभाव के बिना जीवन बचाने में सहायता और दीर्घकालिक पुनर्वास प्रदान करने का प्रयास करते हैं। वे सभी संस्कृतियों, विचारधाराओं और पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करते हैं और मानवतावाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से वे एकजुट हो जाते हैं। इस तरह की मानवतावादी सहायता मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता सहित कई संस्थापक सिद्धांतों पर आधारित है। मार्टिन लूथर किंग ने इसकी उपयोगिता को उजागर करते हुए कहा कि यह प्यार और स्नेह है, जो हमारी दुनिया और हमारी सभ्यता को बचाएगा।ह्न आज अनुभव किया जा रहा है कि देश एवं दुनिया विकृतियों की शूली पर चढ़ा है। नैतिक मूल्यों के आधार पर ही मनुष्य उच्चता का अनुभव कर सकता है और मानवीय प्रकाश पा सकता है। मानव एकता का प्रकाश सार्वकालिक, सार्वदेशिक, और सार्वजनिक है। इस प्रकाश का जितनी व्यापकता से विस्तार होगा, मानव समाज का उतना ही भला होगा। इसके लिए तात्कालिक और बहुकालिक योजनाओं का निर्माण कर उनकी क्रियान्विति से प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। यही विश्व मानव एकता दिवस मनाने को सार्थक बना सकता है।

सनातन सम्मान के लिए भी संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शित होनी चाहिए

पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो हो या हिंदुस्तान का ओवैसी प्रत्येक मुस्लिम नेता ० इस्लामिक धर्म प्रचारक पुरे विश्व के मुसलमानों को गुजरात दंगों व अयोध्या के विवादित ढांचे पर भ्रमित कर मुसलमानों को मजहब के नाम पर संगठित होकर मानवता के विरुद्ध जिहाद करने की ओर प्रोत्साहित करते रहते हैं । जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध निरंतर आपत्तिजनक टिप्णिया की जा रही हैं वस्तुतः यह उन लोगो की खीज है जो भारत में तुष्टिकरण की राजनीति करके भारत की मूल आत्मा सत्य सनातन धर्म पर प्रहार कर मानवता रक्षा की विचारधारा को समाप्त करना चाहते हैं । निसंदेह मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शसक्त हो रहा है व आंतरिक स्तर भी मजहबी कटटरपंथियो ० उनके समर्थको की कमर तोड़ रहा है परन्तु आवश्यकता इस बात की भी है की जब भी कोई भारत की मूल आत्मा व आधार पर हमला करे तो राष्ट्रवादियों को सामूहिक रूप से उसका विरोध करना चाहिए । जिस प्रकार मोदी जी के समर्थन ० बिलावल भुट्टो के विरोध में राष्ट्रवादी लोग सड़को पर आ गए ठीक उसी प्रकार मोदी जी ० असंख्य सनातनियो के आराध्य भगवान भोले नाथ के शिवलिंग को जब कोई गुमांग लिंग कहता हो , देवी माँ के अभद्र चित्र बनाता हो उनकी प्रतिमाओं को खंडित करता हो ,सनातन धर्म की आस्थाओ को जब चलचित्र के माध्यम से अपमानित किया जा रहा हो , बच्चियों को मजहब के नाम पर दूषित कर उनकी निर्मम हत्या की जा रही हो तब भी राष्ट्रवादियों को संगठित होकर विरोध करना चाहिए क्यूंकि इसी मजहबी उत्पीड़न से बचाव के लिए भारत की जनता ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़कर भाजपा को सत्ता प्रदान की है । अतः भाजपा संगठन ० जनप्रतिनिधियो की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है की वह उन सभी लोगो की भावनाओ के अनुरूप अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें जिन लोगो के मतों से भाजपा ने सत्ता प्राप्त की है।

सामाजिक नीति के बजाय जाति आधारित वोट-बैंक की राजनीति

ग्राम स्तर पर भी पंचायत राज चुनावों में जाति व्यवस्था हावी रही है। जोधपुर संभाग में चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों जैसे जाटों को आरक्षण आदि के लिए पार्टियां चलती हैं। इसी तरह उड़ीसा में भूमिहार, कायस्थ और राजपूत चुनाव के समय अलग-अलग दिशाओं में खींचते हैं और अपनी जाति के उम्मीदवारों को कार्यालय में देखने की इच्छा रखते हैं। जाति भारत में राजनीति को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इसका प्रभाव अधिक बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से है। स्वतंत्र भारत में यह आशा की जाती थी कि जाति धीरे-धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर देगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं और जाति अभी भी राजनीति को प्रभावित करती है।

डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था अपने सबसे सामान्य लेकिन मूलभूत पहलुओं में स्थिति और पदानुक्रम की एक आरोपित प्रणाली है। यह व्यापक और सर्वव्यापी है और व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करने और परिभाषित करने के लिए जाना जाता है। राजनीति एक प्रतिस्पर्धी उद्यम है, इसका उद्देश्य कुछ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए शक्ति का अधिग्रहण है और इसकी प्रक्रिया स्थिति को संगठित और समेकित करने के लिए मौजूदा और उभरती हुई निष्ठाओं की पहचान और हेरफेर करने में से एक है। उसके लिए जो आवश्यक है वह है संगठन और समर्थन की अभिव्यक्ति, और जहाँ राजनीति जन आधारित है, बिंदु उन संगठनों के माध्यम से समर्थन को स्पष्ट करना है जिनमें जनता पाई जाती है।

वोट बैंक की राजनीति पहले भी होती थी, लेकिन जैसे-जैसे दलों की संख्या बढ़ती गई और जाति विशेष की राजनीति करने वाले दल बनने लगे, वैसे-वैसे यह राजनीति और गहन होती गई। हाल के समय में जाति-संप्रदाय और क्षेत्र विशेष के सहारे राजनीति करने वाले दलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थिति यह है कि राज्य विशेष में चार-पांच प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली जाति समूह के नेता भी अपना-अपना दल बना रहे हैं। इसकी एक वजह राजनीति में प्रतिनिधित्व हासिल करना और सत्ता में भागीदारी करना भी है। भारतीय समाज में जाति की गहरी पैठ होने के बाद भी यह ठीक नहीं कि लोग अपने मतदान का निर्धारण जाति-संप्रदाय के आधार पर करें। दुर्भाग्य से ऐसा ही होता आ रहा है और इसलिए गोवा, मणिपुर से लेकर पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दल जाति-संप्रदाय विशेष पर डोरे डालने में लगे हुए हैं। कुछ जातीय समूहों के बारे में तो यह मानकर चला जा रहा है कि वे अमुक दल के पक्के वोट बैंक हैं।

दूसरी ओर, भारत में, ऐसे समूह-जातियाँ और उप-जातियाँ सामाजिक जीवन पर हावी हैं, और अनिवार्य रूप से एक सामाजिक या राजनीतिक चरित्र के अन्य समूहों के प्रति अपने सदस्यों के रवैये को प्रभावित करती हैं। दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि एक जाति एक प्रभावी दबाव समूह के रूप में कार्य करने में सक्षम है, और यह कि इसके सदस्य इसे छोड़कर अन्य समूह में शामिल नहीं हो सकते, इसे एक राजनीतिक शक्ति की स्थिति में रख देता है, जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं की सद्भावना पर अपने जनादेश के आधार पर राजनीतिक दल भारत में जाति आधारित चुनावी राजनीति जाति लोकतांत्रिक राजनीति के संगठन के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करती है। एक खुली राजनीति में समर्थन को व्यवस्थित करने और स्पष्ट करने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से उन संगठनों और एकजुटता समूहों की ओर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है जिनमें जनता पाई जाती है। भारत जैसे समाज में जहां जाति सामाजिक संगठन और गतिविधि का प्रमुख आधार बनी हुई है, इसका अर्थ जाति समूहों और संघों की ओर मुड़ना है।

इस तरह जातिगत पहचान और एकजुटता प्राथमिक चैनल बन गए जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के भीतर चुनावी और राजनीतिक समर्थन जुटाया जाता है। इस प्रकार, जैसा कि कोठारी कहते हैं, ह्यह राजनीति नहीं है जो जाति से ग्रस्त हो जाती है, यह जाति

है जो राजनीति हो जाती है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन जुटाने में जाति का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। राजनीतिक दलों के लिए किसी जाति समुदाय के सदस्यों से अपील कर-के उनसे सीधे समर्थन जुटाना आसान हो जाता है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था स्वयं अनुयायियों के प्रजनन के साधन के रूप में जाति के उपयोग को प्रोत्साहित या बाधित करती है। जैसेः बसपा, एआईएमआईएम आदि इसके उदाहरण हैं, हाल ही में यह तर्क दिया गया है कि जाति भारत के निरक्षर और राजनीतिक रूप से अज्ञानी जनता को आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाती है।

उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के बजाय उनकी जाति के आधार पर चुना जा रहा है। एक जाति के भीतर विचारों का संचार मजबूत होता है और आम तौर पर एक जाति के सदस्य राजनीतिक दलों, राजनीति और व्यक्तियों के संबंध में समान विचार साझा करते हैं। शोध के अनुसार यह सामान्य पैटर्न है कि उच्च जाति के हिंदू भाजपा को वोट देते हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों को वोट देते हैं। आरक्षण प्रणाली को भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय वोट बटोरने के लिए आरक्षण के नाम पर अधिक सामान दिए जाते हैं, जिसने आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर दिया है। इसलिए, जिसे मूल रूप से एक अस्थायी सकारात्मक कार्य-योजना (विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की स्थिति में सुधार करने के लिए) माना जाता था, अब कई राजनीतिक नेताओं द्वारा वोट हथियाने की कवायद के रूप में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

ग्राम स्तर पर भी पंचायत राज चुनावों में जाति व्यवस्था हावी रही है। जोधपुर संभाग में चुनाव के दौरान जाति आधारित मुद्दों जैसे जाटों को आरक्षण आदि के लिए पार्टियां चलती हैं। इसी तरह उड़ीसा में भूमिहार, कायस्थ और राजपूत चुनाव के समय अलग-अलग दिशाओं में खिंचते हैं और अपनी जाति के उम्मीदवारों को कार्यालय में देखने की इच्छा रखते हैं। जाति भारत में राजनीति को प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि इसका प्रभाव अधिक बलपूर्वक और प्रभावी ढंग से है। स्वतंत्र भारत में यह आशा की जाती थी कि जाति धीरे-धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर देगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं और जाति अभी भी राजनीति को प्रभावित करती है। स्वतंत्र भारत में जहां राज्य जातिविहीन समाज में रुचि रखता था लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि जाति राजनीति और चुनाव दोनों को अधिक से अधिक प्रभावित कर रही है।

केंद्र अथवा राज्यों में सत्ता में आने वाली सरकारें पिछड़ी और वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनेक उपायों के साथ दर्जनों योजनाओं का संचालन करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सबसे उन जातियों का अपेक्षित हित नहीं हो पा रहा है। सब जानते हैं कि जातियों के खांचे में बंटा हुआ समाज तेज गति से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जाति का मसला राजनीति व शासन-प्रशासन के लिए इतना अधिक संवेदनशील बन गया है कि उसमें हेरफेर के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी।

जाति व्यवस्था से ज्यादा हीन या श्रेष्ठ मानना एक समस्या है

जाति आधारित व्यवसाय कोई समस्या नहीं है लेकिन एक व्यवसाय को हीन या श्रेष्ठ मानना एक समस्या है। हर पेशे का सम्मान होना चाहिए। महात्मा गांधी की ह्लब्रेड लेबरह्व (हर किसी को कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए) और ह्लट्रस्टीशिपह्व (पूंजीपतियों का समाज के प्रति ऋण) की अवधारणा इसी पर आधारित है। इससे जाति आधारित समस्याओं को एक हद तक कम किया जा सकता है। लोगों के दिमाग से अंतर्विवाह और शुद्ध रक्त की प्रथा को मिटा देना चाहिए। सभी को जाति, धर्म या किसी अन्य पहचान के बावजूद व्यक्ति से विवाह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह पहचान आधारित समस्याओं को भी कम कर सकता है। जाति व्यवस्था कोई अभिशाप नहीं है। लेकिन एक जाति को श्रेष्ठ या प्रभुत्वशाली मानने को बंद कर देना चाहिए। जाति को निजी स्थान तक सीमित रखा जाना चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। साक्षरता का स्तर बढ़ाना और मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकता है या निजी स्थान तक सीमित कर सकता है।

जाति भारत में वर्ण व्यवस्था के रूप में पूर्व-आधुनिक युग में उत्पन्न सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है। वर्ण व्यवस्था केवल उस व्यवसाय पर आधारित है जो ब्राह्मण (पुजारी), क्षत्रिय (गार्ड), वैश्य (व्यापारी), और शूद्र (सीवेज कार्यकर्ता) का काम करता है। जाति जो व्यवसाय की पहचान के रूप में उत्पन्न हुई बाद में जन्म पहचान में बदल गई। स्वतंत्रता के दौरान भारत में जाति व्यवस्था भयानक थी और समाज के हर क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा और अछूत नामक नया शब्द इस युग में अस्तित्व में आया। भारत के सामाजिक कार्यकताओं और दार्शनिकों ने जाति की इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उदाहरण के लिए ज्योतिराव फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जाति और इसकी व्याख्याओं का विरोध किया और उन्होंने हिंदू संदर्भ में निमार्ता के अस्तित्व के बारे में तर्क दिया। यदि निमार्ता ब्रह्मा चाहते कि मनुष्य जाति व्यवस्था के अधीन हों तो क्यों जानवरों और पक्षियों जैसी अन्य प्रजातियां नहीं।

विवेकानंद ने जाति की मनुष्य की संस्थाओं में से एक के रूप में आलोचना की, जो व्यक्ति के मुक्त विचार और कार्रवाई की शक्ति को रोकती है। यह शैतानी है और इसे नीचे खत्म होना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार विचार और कार्रवाई की स्वतंत्रता, विकास और विकास के जीवन की एकमात्र शर्त है। गांधीजी हालांकि अंबेडकर के जाति और आरक्षण के विचारों से असहमत थे, उन्होंने दावा किया कि जाति ने हिंदू धर्म को विघटन से बचाया है, लेकिन हर दूसरी संस्था की तरह यह एक्सरेस्स से पीड़ित है। वे चार वर्णों को मौलिक, नैत्रृत्य और आवश्यक मानते हैं। असंख्य जातियों या उपजातियों को एक बाधा माना जाता है। उन्होंने जाति में आनुवंशिकता की अस्वीकृति की वकालत की और तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य पर श्रेष्ठता की धारणा भगवान और मनुष्य के खिलाफ पाप है, और वर्तमान जाति व्यवस्था वर्णाश्रम का सिद्धांत विरोधी है। और जाति का अपने वर्तमान स्वरूप धर्म के साथ से कोई लेना-देना नहीं है।

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले विपुल लेखक और प्रमुख व्यक्ति अम्बेडकर का जन्म एक अनुसूचित जाति परिवार में हुआ था, जिसे अछूत समुदाय के रूप में वगीर्कृत किया गया था, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की और अछूतों का वर्णन किया क्योंकि वे एक ही धर्म और संस्कृति से संबंधित हैं, फिर भी वे जिस समुदाय में रहते थे, उससे दूर और बहिष्कृत थे। उनके अनुसार अछूत पवित्र हैं और भारत के धर्मनिरपेक्ष कानूनों को मान्यता देते हैं। लेकिन वे समाज से अलग कर दिए जाते हैं और गांवों के बाहरी इलाकों में रहते हैं, जीवित रहने की निम्न स्थिति में आ जाते हैं। जाति व्यवस्था अम्बेडकर ने देखा कि एक व्यक्ति को जन्म से ही अछूत माना जाता था और उसकी निम्न सामाजिक स्थिति तय की गई थी। अम्बेडकर का मत था कि उनके समय में जाति व्यवस्था सार्वभौमिक रूप से निरपेक्ष नहीं थी। अम्बेडकर द्वारा सूचीबद्ध जाति व्यवस्था लोगों को अलग-थलग करती है, निम्न जाति के व्यक्तियों में हीन भावना का संचार करती है और मानवता को विभाजित करती है। इसने भारत के लोगों को भारत के विकास और ज्ञान को साझा करने से रोका और स्वतंत्रता के फल बनाने और आनंद लेने की क्षमता को नष्ट कर दिया। यदि हम धर्म और जाति द्वारा जनसंख्या वितरण के आंकड़ों को देखें तो भारत के प्रमुख धर्म में जाति के सभी वर्गों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, यानी 22.2% एससी, 9% एसटी और 42.8% ओबीसी, जबकि यह अगड़ी जाति का 26% है। कई अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म के बाद भी विभिन्न जातियों में उनका वितरण होता है।

औपनिवेशिक काल के दौरान अस्पृश्यों की स्थिति आमतौर पर उनके निचले स्तर से ऊपर थी, लेकिन बहुसंख्यकों के पास सीमित गतिशीलता थी। जातियों ने लोगों को केवल विघटित करने और असंख्य विभाजनों का कारण बनने के लिए विभाजित किया जो लोगों को अलग-थलग कर देते थे और भ्रम पैदा करते थे। जाति के अभिशाप ने समाज के लिए कई मानवीय नुकसान साबित किए। स्वतंत्र भारत ने 2005 की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जाति-संबंधी हिंसा देखी है, 1996 में दलितों के खिलाफ किए गए हिंसक कृत्यों के लगभग 31440 मामले दर्ज किए गए थे।

दूध की सूखती धार

दूध पौष्टिकता का प्रतीक है। दूध देवताओं को प्रिय है। दूध अमृत है। दूध शाकाहारियों के लिए प्राथमिक प्रोटीन का स्रोत है। दूध विटामिन डी का एक दुर्लभ खाद्य स्रोत भी है। पुराणों में दूध की तुलना अमृत से की गई हैं, जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के साथ-साथ कई सारी बीमारियों से बचाता है। अथर्ववेद में लिखा है कि दूध एक सम्पूर्ण भोज्य पदार्थ है। इसमें मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक वे सभी तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। दूध की शुद्धता अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है। भारत को सदियों से दूध दही का देश कहा जाता रहा है। पंजाब और हरियाणा दुग्ध उत्पादन में हमेशा आगे रहे हैं। एक प्रचलित कहावत है कि जहां दूध दही का खाना वो है हमारा हरियाणा। अब खपत को पूरा करने के लिए इसी दूध में जहर को घोला जा रहा है। मिलावटी दूध हमारे स्वास्थ्य और जीवन को नरक में धकेल रहा है। दूध में मिलावट का सबसे बड़ा कारण देश में दूध की धार का सूखना है। देश में सबसे ज्यादा डेयरियां हैं फिर भी अब दूध की कमी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में कुल 671.919 टन दुग्ध का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में वर्ष 2022 में दूध का अनुमानित उत्पादन 800 टन (7 लाख 76 हजार 699 लीटर) के आस पास है। वर्ष 2022 में प्रयागराज की अनुमानित जनसँख्या लगभग 69 लाख है। जबकि दूध की प्रतिव्यक्ति खपत लगभग 500 मिलीलीटर है। कहने का तात्पर्य 7 लाख लीटर दूध 14 लाख की जनसंख्या की खपत को ही पूरा कर सकता है न की 69 लाख की जनसँख्या की खपत को पूरा करेगा। प्रयागराज शहर में दुग्ध उत्पादन से खपत 5 गुना ज्यादा है। ये खपत कैसे पूरी हो रही है इसकी जांच होनी चाहिए। जाहिर है कि ये खपत दूध की धार में सफेद जहर मिलाकर पूरी की जा रही है। भारत में दूध का उत्पादन 20 करोड़ लीटर लेकिन खपत 70 करोड़ लीटर है। इससे साबित होता है की दूध में मिलावट बड़े पैमाने पर हो रही है। देश में मिलावटी दूध से खपत को पूरा किया जा रहा है। दक्षिणी राज्यों के मुकाबले उत्तरी राज्यों में दूध में मिलावट के ज्यादा मामले सामने आए हैं। हद तो तब हो गई जब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) ने दुग्ध उद्योगों को मेलामाइन मिलाने की अनुमति दे दी। जिसके अनुसार सूखे दूध का इन्फेंट फामूर्ला (शिशु दूध) बनाने वाली कोई भी कंपनी 1 किलोग्राम सूखे दूध में 1 मिली ग्राम मेलामाइन मिला सकती है। लिक्विड इन्फेंट फामूर्ला जैसे कि लिक्विड मिल्क (तरल दूध) में यह 0.15 मिली ग्राम/लीटर और अन्य खाद्य पदार्थों में 2.5 मिली ग्राम/किलोग्राम के हिसाब से मेलामाइन नाम का जहर मिलाने की खुली छूट है। मेलामाइन एक कार्बन आधारित रसायन होता है, जिसे दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिये प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि दूध और डेयरी उत्पादों में मेलामाइन की मिलावट करने से गुर्दे संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं और गुर्दा पूर्णतः खराब भी हो सकता है। कई बार दूध के व्यापारी दूध की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें पानी मिला देते हैं, जिससे दूध में प्रोटीन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इस प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करने के लिये दूध व्यापारियों द्वारा दूध में मेलामाइन मिलाया जाता है। व्यापक तौर पर मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक, गोंद, काउंटरटॉप्स और व्हाइटबोर्ड आदि बनाने के लिये किया किया जाता है। अभी हाल की घटना है एक व्यक्ति ने अमूल के पैकेट वाले दूध को उबालने के बाद प्लास्टिक के रूप में मलाई को पाया। ये मेलामाइन ही है। केंद्र सरकार को मेलामाइन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। अतएव हम कह सकते हैं कि दूध अब जहर बनता जा रहा है। लोग भौतिकता में इतना बह गए हैं कि अमृत को भी जहर बना डाला है। दूध में मिलावट को लेकर कुछ साल पहले देश में एक सर्वे हुआ था। इसमें पाया गया कि दूध को पैक करते वक्त सफाई और स्वच्छता दोनों से खिलवाड़ किया जाता है। दूध में डिटर्जेंट की सीधे तौर पर मिलावट पाई गई। यह मिलावट सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरा साबित हुई। इसके चलते उपभोक्ताओं के शारीरिक अंग काम करना बंद कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूध में मिलावट के खिलाफ भारत सरकार के लिए एडवायजरी जारी की थी और कहा था कि अगर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट में मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश की करीब 87 फीसदी आबादी 2025 तक कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकती है। हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र के समुदाय का स्वास्थ्य ही उसकी संपत्ति है। अतएव राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर भारत को दूध में होने वाले मिलावट के बारे में सोचना होगा और इससे उबरने के लिए भारत सरकार को ठोस रणनीति बनाने की जरुरत है। अब वो दिन दूर नहीं जब लोगो को वेगन मिल्क पर ही निर्भर होना पड़ेगा। पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध के अलावा हर प्रकार का दूध वेगन मिल्क की श्रेणी मे आता है। पश्चिमी देशों में इसका चलन जोरों पर है। अब भारत मे भी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वेगन दूध को पारंपरिक डेयरी प्रोडक्ट के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। सामान्यतः दूध की आपूर्ति गाय और अन्य पशुओं से की जाती है पर वेगन मिल्क को पौधों और अन्य वस्तुओं से तैयार किया जाता है। जैसे सोया मिल्क (सोया का दूध), ओट मिल्क (जई का दूध), बादाम मिल्क (बादाम का दूध), काजू मिल्क (काजू का दूध), राइस मिल्क (चावल का दूध), कोकोनट मिल्क (गरी का दूध) इत्यादि। यदि अमृत में जहर घोला जाता रहेगा तो अमृत रूपी पारम्परिक दूध के विलुप्त होने में समय नहीं लगेगा। एक पुरानी कहावत है कि हम जीने के लिए खाते हैं न कि खाने के लिए जीते हैं। आप खाने के लिए जीवित मत रहिये। जीवित रहने के लिए खाइये। जीवित रहने के लिए आपको शुद्ध भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा न की जहर पर। कहने का तात्पर्य है कि जब हम जीने के लिए खाते हैं तो अच्छा और कम खाते हैं और जब हम खाने के लिए जीवित रहते हैं तो खराब और ज्यादा खाते हैं। कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। अतएव थोड़ा खाएं पर अच्छा खाएं। दूध थोड़ा ही पीयें पर अच्छा पीयें। ज्यादा के चक्कर में जहर न पीयें।

आमदनी पर कम कैसे हो टैक्स

सरकार की बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि एक तरफ ढ़ाई लाख से ऊपर की कमाई पर आयकर और दूसरी तरफ आठ लाख से कम कमाने वाला आर्थिक रूप से कमजोर, यह उलटबांसी कैसे चलेगी? मद्रास हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका दायर कर मांग की गई है कि आठ लाख रुपये तक की आमदनी को करमुक्त किया जाए। अदालत ने इस पर सरकार को नोटिस भेजा है और सुनावाई के लिए अगले माह की तारीख दी है।

पिछले सोमवार से वित्त मंत्री ने सरकार के बाहर के आर्थिक विशेषज्ञों और तमाम ऐसे लोगों के साथ बजट-बैठकें शुरू कर दी है जिन पर बजट का असर पड़ता है। बजट का नाम सुनते ही मध्यम वर्ग के मन में टैक्स का सवाल उठने लगता है। अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों को छोड़ दें, तो कुछ साल पहले तक आम आदमी दो चीजें समझने के लिए ही बजट देखा या पढ़ा करता था। क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ और दूसरा आयकर में क्या घटा और क्या बढ़ा। जीएसटी लागू होने के बाद महंगे-सस्ते का खेल करीबन बंद हो चुका है, लेकिन अभी आयकर के मामले में उम्मीद के दरवाजे खुले हुए हैं। आयकर रिटर्न की बारीकियों को जानकर हम अपनी आमदनी पर टैक्स को कम कर सकते हैं।

आयकर की गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होती है तथा इस दौरान प्राप्त आय इस वित्तीय वर्ष की मानी जाती है। वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए आधार होता है। चूंकि किसी वर्ष की आय पर आयकर का निर्धारण वर्ष समाप्ति के पश्चात अगले वर्ष किया जाता है अतः अगले वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। इसलिये जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उस वर्ष को गतवर्ष के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः माह मार्च का वेतन 1 अप्रैल को तथा आगामी वर्ष के फरवरी माह का वेतन मार्च को प्राप्त होता है इसलिये मार्च से आगामी वर्ष की फरवरी माह तक के वेतन को आयकर विवरणिका में शामिल किया जाता है। फिर भी वेतन की गणना करने के लिये यह देखना होगा कि वेतन कब उपार्जित हुआ है अथवा कब प्राप्त हुआ है, इन दोनों परिस्थितियों में जो भी पहले हो के अनुसार उसके अनुसार कर योग्य माना जाएगा।

आयकर वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र हैं, और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है।

यदि गतवर्ष में कोई पिछला वेतन प्राप्त हुआ है तथा उस पर सम्बन्धित वर्ष में उपार्जन के आधार पर कर नहीं लगा है तो उस पर प्राप्ति के आधार पर कर लगाया जाएगा। यदि गतवर्ष में उपार्जित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तो उस पर गतवर्ष में ही कर लगाया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता ने अग्रिम वेतन दिया है तो वह प्राप्ति वाले वर्ष में टैक्स देय होगा। गतवर्ष में कोई एरियर प्राप्त हुआ है तो वह भी गतवर्ष में कर योग्य होगा बशर्ते वह राशि उपार्जित होने वाले वर्ष में पहले ही कर योग्य न की गई हो। किन्तू एरियर पर धारा 89 की छूट का दावा किया जा सकता है। यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कोई बोनस, कमीशन अथवा फीस प्राप्त होती है तो वह जिस वर्ष में प्राप्त होगी वह वेतन के अन्तर्गत ही प्राप्ति वर्ष में कर योग्य होगी।

सभी राजकीय कर्मचारियों एवं गैर राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाली मासिक पेंशन पूर्णतः कर योग्य होगी। यह देय होने वाले वर्ष में कर योग्य होगी। एक सरकारी कर्मचारी को राजसेवा में रहते हुए यदि अवकाश के बदले कोई नकदीकरण होता है तो पूर्णत कर योग्य होगा। तथा यदि सेवानिवृत्ति पर राजकीय कर्मचारी अवकाश के बदले नकदीकरण प्राप्त होता है तो वह राशि पूर्णतयः कर मुक्त होगी।

वेतन में मूल वेतन, मंहगाई वेतन, ग्रेड-पे, अवकाश वेतन, अग्रिम वेतन, वकाया वेतन, नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान, बोनस, कमीशन, फीस, विशेष वेतन, निर्वाह भत्ता आदि सम्मिलित किये जाते है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, सीसीए, प्रतिनियुक्ति भत्ता, अंतरिम राहत, एनपीए, नौकर भत्ता, मेडिकल भत्ता, परियोजना भत्ता ओवरटाईम भत्ता, वार्डन भत्ता, टिफिन भत्ता (मकान किराया कुछ परिस्थितियों में कर मुक्त है)। आफिस कार्य हेतु आने-जाने, आफिस कार्य या ट्रांसफर के लिये की गयी यात्रा, आफिस के कार्य के निष्पादन हेतु हैल्पर रखने, अनुसंधान खर्च एवं पोशाक भत्ता वास्तविक व्यय की सीमा तक कर मुक्त होंगे।

आयकर में राहत की उम्मीद पालना गलत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सरकार पहले अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कठोर कदम उठाती है, फिर चुनाव नजदीक आने पर लोक-लुभावन बजट पेश करती है। इसीलिए चुनाव से पहले के वर्षों में उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना-काल में जहां देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार को झटका लगा, वहीं आम आदमी की जेब और परिवार के बजट को भी चोट पहुंची। सरकार ने उद्योगों, व्यापारियों, गरीबों, यहां तक कि ईएमआई भुगतान करने वाले लोगों को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की, पर जो लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, पूरा टैक्स चुकाते हैं, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं है, उनको बेसहारा छोड़ दिया। पिछले दो साल तो उन्होंने सब्र कर लिया, लेकिन इस साल जब महीने-दर महीने रिकार्डतोड़ टैक्स वसूली की खबरें आ रही हैं, तो उन्हें लगता है कि अब सरकार इस हाल में उनकी भी सुध ले।

सरकार को करमुक्त आमदनी की सीमा बढ़ानी चाहिए और टैक्स स्लैब को भी ऊपर उठाने चाहिए। यह सोचने वाले सिर्फ मध्यम वर्ग के लोग नहीं है। भारत के धनी उद्योगपतियों का संगठन सीआईआई भी वित्त मंत्री से अपनी बजट-चर्चा में सलाह दी है कि सरकार आयकर में कटौती स्लैब में बदलाव पर विचार करें। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में मांग बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है जब भी आयकर में छूट या राहत दी जाती है तो यह बाजार में खपत बढ़ाने में मददगार होती है। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि वित्त मंत्री इस बार मध्यवर्ग को, खासकर नौकारीपेशा लोगों को खुशखबरी दे सकती हैं।

स्त्री अत्याचारों से जुड़ी चिन्ताओं की टंकार

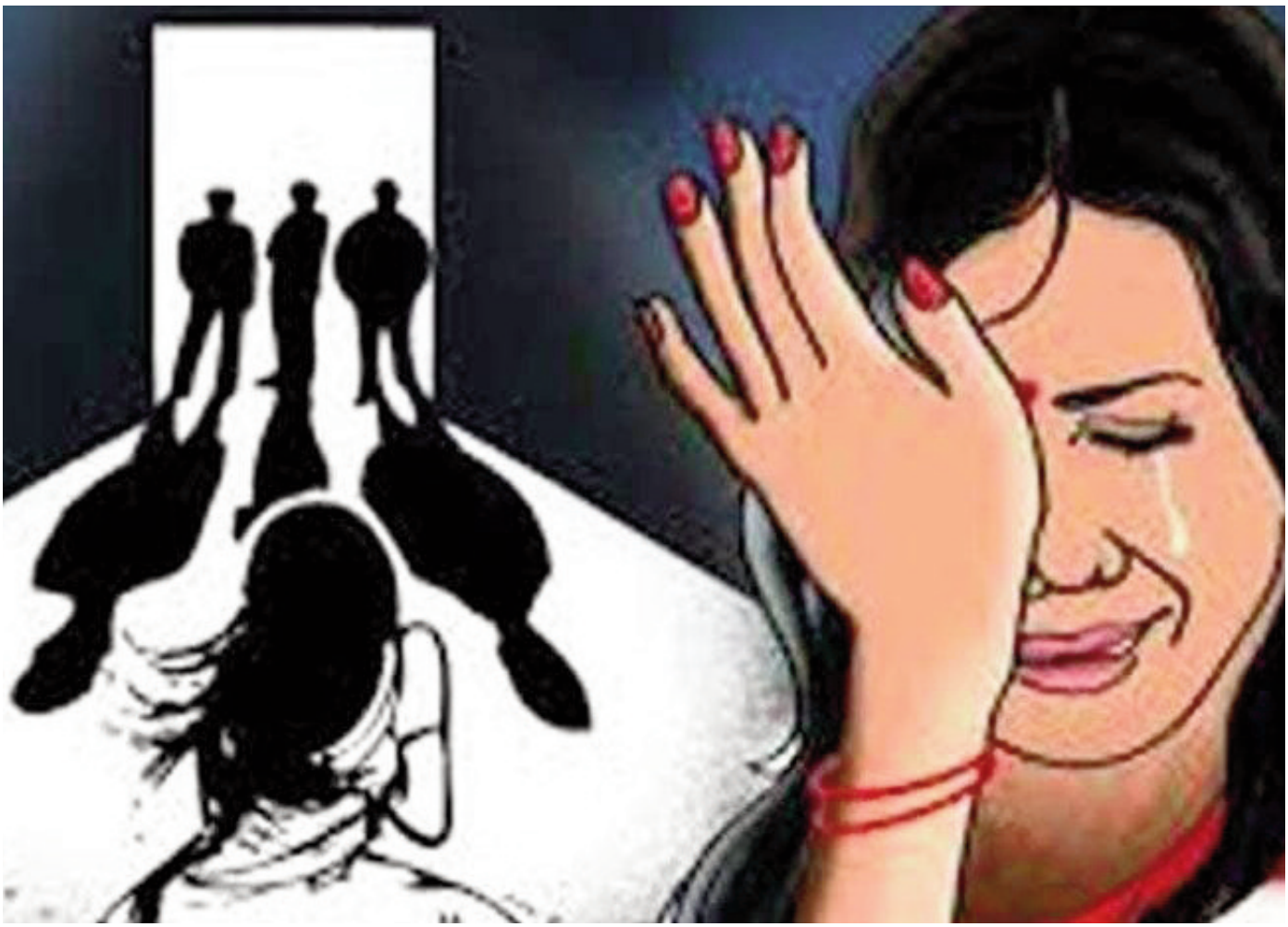

इनदिनों स्त्रियों के घरेलू जीवन में उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। विशेषतः कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान एवं उसके बाद महिलाओं पर हिंसा, मारपीट एवं प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसी ही पीलीभीत की एक घटना ने रोंगटे खड़े कर दिये। खाने में बाल निकलने के बाद पत्नी को पीलीभीत के युवक जहीरुद्दीन ने जिस बेरहमी, बर्बरता एवं क्रूरता से मारा, जमीन पर गिरा दिया, घर में रखी बाल काटने वाली मशीन (ट्रिमर) को पत्नी के सिर पर चला दिया, इन दुभाग्यपूर्ण एवं शर्मसार करने वाली नृशंसता की घटना की जितनी निन्दा की जाये, कम है। स्त्री को समानता का अधिकार देने और उसके स्त्रीत्व के प्रति आदर भाव रखने के मामले में आज भी पुरुषवादी सोच किस कदर समाज में हावी है,क इसकी पीलीभीत की यह ताजा घटना निन्दनीय एवं क्रूरतम निष्पत्ति है। दुभाग्यपूर्ण पहलू यह है कि जब एक स्त्री पर यह अनाचार हो रहा था तो दूसरी स्त्री यानी उसकी सास भी खड़ी थी और उसके बचाव में नहीं आई। जब उक्त युवक को अपने अपराध का अहसास हुआ तो भी वह पश्चाताप करने के बजाय पत्नी को ऐसे ही बंधा छोड़कर फरार हो गया। रह-रह कर समाज में घटित हो रही ये महिला अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न की घटनाएं चिन्तित करती एवं इन पर नियंत्रण के लिये कुछ प्रभावी कदमों की जरूरत व्यक्त करती है।

यह देखना भी दिलचस्प है कि जहां साल में दो बार लड़कियों को महत्व देने के लिए उसे पूजने के पर्व मनाए जाते हों, वहां लड़कियों को दोयम दर्जे का मानने वाले भी बहुत हैं, महिलाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता को नौंचने वाले भी कम नहीं है, आये दिन ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं कि किस तरह आज भी महिलाओं के साथ हिंसा एवं अत्याचार किया जाता है। जबकि आधुनिक होते भारत में महिलाओं ने अपने प्रयास के दम पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह देखकर गर्व होता है लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसी पीलीभीत में हुई, तो यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि समाज की वास्तविकता क्या है? महिला समानता आज का सच है या अपवाद? प्रगति के प्रतिमान लिखने वाली महिलाएं हमारे समाज का वास्तविक सच हैं या वह, जो पीलीभीत की पीड़िता के साथ हुआ। इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा।

महिलाओं के प्रति यह संवेदनहीनता एवं बर्बरता कब तक चलती रहेगी? भारत विकास के रास्ते पर तेजी

से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में महिलाओं को लेकर गलत धारणा है कि महिलाएं या बेटियां परिवार पर एक बोझ की तरह हैं। एक विकृत मानसिकता भी कायम है कि वे भोग्य की वस्तु है? उन्हें पांव के नीचे रखा जाना चाहिए। यों यह घटना आए दिन होने वाले जघन्य अपराधों की ही अगली कड़ी है, मगर यह पुरुषवादी सोच और समाज के उस ढांचे को भी सामने करती है, जिसमें महिलाओं की सहज जिंदगी लगातार मुश्किल बनी हुई है, संकटग्रस्त एवं असुरक्षित है। भले ही महिलाओं ने अपनी जंजीरों के खिलाफ बगावत कर दी है, लेकिन देश में ऐसा वर्ग भी है जहां आज भी महिलाएं अत्याचार का शिकार होती है। भले एक खास महिला वर्ग ने आर्थिक मोर्चे पर आजादी हासिल की है, लेकिन एक बड़ा महिला वर्ग आज भी पुरुषप्रधान समाज की सोच की शिकार है। ऐसा कायम है तभी आजादी के अमृत महोत्सव मना चुके राष्ट्र की तमाम महिलाएं ह्यमुझे पति और पति के परिवार से बचाओह्न की गुहार लगातीं हुई दिखाई देती है। इसलिये कि उन्हें सदियों से चली आ रही मानसिकता, साजिश एवं सजा के द्वारा भीतरी सुरंगों में धकेल दिया जाता है, अत्याचार भोगने को विवश किया जाता है।

महिलाएं सभी समाजों, सभी देशों और सभी कालों में महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। चाहे वेदों की बात करें, जो महिलाओं को पूजनीय बताते हैं, या गांधीजी की बात करें जो उन्हें परिवार की धूरी बताते हैं, हर समय महिलायें महत्वपूर्ण रही हैं। वेद कहते हैं कि वह व्यवस्था सबसे उत्तम है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है। गांधीजी मानते थे कि अगर पूरे परिवार को और आगे आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाना है, तो केवल उस परिवार की महिलाओं को शिक्षित कर देना चाहिये। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्न अभियान की शुरूआत हरियाणा के पानीपत जिले से की थी। इसके बाद भ्रूण हत्या को समाप्त करने व महिलाओं से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर पुरुष मानसिकता में व्यापक परिवर्तन आया है। लेकिन व्यापक परिवर्तन ही नहीं, आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। प्रश्न है कि घर की चार-दीवारी के भीतर महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला कब रूकेगा?

आखिर कब तक महिलाओं की छोटी-छोटी भूलों के लिये पुरुष उनको पिटते रहेंगे? क्यों हर कदम पर पुरुष व्यवस्था द्वारा लगाये गये नियमों के पालन में थोड़ी-सी कोताही उसे अपराधिनी सिद्ध करने का आधार बनती रहेगी। सेवा, श्रम और सेक्स-ये तीन बातें स्त्री के जीवन के आधार स्तंभ है, जो उसे परिवार और पति के लिये समर्पित करने हैं। इनमें तनिक चूक के लिये वह हिंसा की शिकार बना दी जाती है। लेकिन इन अत्याचारों को सहते-सहते स्त्री टूट चुकी है। आज त्याग की जंजीरें और सहने की ताकत की कड़ियां बिखर चुकी है। स्त्री का विद्रोही स्वरूप सामने आ रहा है, विवाह का विधान डगमगाने लगा है, समाज के सामने खतरे की घंटी बज रही है। आखिर इसका जिम्मेदार पुरुष ही है, उसके बढ़ते अत्याचार है, स्त्री को दोयम दर्जा मानने की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता चाहे पीलीभीत में कहर ढाये या अन्यत्र। असर पूरे महिला समाज पर होता है। सवाल यह है कि औरत को तरह-तरह से घेरने वाली सजायें एवं जुल्म जब गुजरते हैं तो ह्यऐसा तो होता ही रहता हैह्न की मान्यता अब स्त्री

महिलाएं सभी समाजों, सभी देशों और सभी कालों में महत्वपूर्ण भूमिका में रही है। चाहे वेदों की बात करें, जो महिलाओं को पूजनीय बताते हैं, या गांधीजी की बात करें जो उन्हें परिवार की धूरी बताते हैं, हर समय महिलायें महत्वपूर्ण रही हैं। वेद कहते हैं कि वह व्यवस्था सबसे उत्तम है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है। गांधीजी मानते थे कि अगर पूरे परिवार को और आगे आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाना है, तो केवल उस परिवार की महिलाओं को शिक्षित कर देना चाहिये। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्न अभियान की शुरूआत हरियाणा के पानीपत जिले से की थी। इसके बाद भ्रूण हत्या को समाप्त करने व महिलाओं से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर पुरुष मानसिकता में व्यापक परिवर्तन आया है।

को स्वीकार्य नहीं है। जुल्म भले एक महिला को झेलना पड़े लेकिन अनेक महिलाएं उससे जागरूक हो जाती है, कमर कस लेती है। निश्चिय ही यह पुनः एक प्रश्न को जन्म देता है कि क्या महिलायें अभी भी दोयम दर्जे की है?

नरेन्द्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोयम दर्जा का लेबल हट रहा है। हिंसा एवं अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है। बड़ी संख्या में छोटे शहरों और गांवों की लड़कियां पढ़-लिखकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे उन क्षेत्रों में जा रही हैं, जहां उनके जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। वे टैक्सी, बस, ट्रक से लेकर जेट तक चला-उड़ा रही हैं। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रही है। अपने दम पर व्यवसायी बन रही हैं। होटलों की मालिक हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लाखों रुपये की नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। वे विदेशों में पढ़कर नौकरी नहीं, अपने गांव का सुधार करना चाहती हैं। अब सिर्फ अध्यापिका, नर्स, बैंकों की नौकरी, डॉक्टर आदि बनना ही लड़कियों के क्षेत्र नहीं रहे, वे अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इस तरह नारी एवं बालिका शक्ति ने अपना महत्व तो दुनिया समझाया है, लेकिन नारी एवं बालिका के प्रति हो रहे अपराधों में कमी न आना, घरेलू हिंसा का बढ़ना- एक चिन्तनीय प्रश्न है। सरकार ने सख्ती बरती है, लेकिन आम पुरुष की सोच को बदलने बिना नारी एवं बालिका सम्मान की बात अधूरी ही रहेगी। इस अधूरी सोच को बदलना नये भारत का संकल्प हो, इसीलिये तो इस देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू को आसीन किया गया हैं। वह प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अमेरिका आज तक किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं बना सका, जबकि भारत में इंदिरा गांधी तो 1966 में ही प्रधानमंत्री बन गई थीं। असल में, यही तो स्त्री शक्ति की असली पूजा है। अब स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान भावना ही नहीं, सह-अस्तित्व एवं सौहार्द की भावना जागे, तभी उनके प्रति हो रहे अपराधों में कमी आ सकेगी। तभी पीलीभीत जैसी बर्बर मानसिकता पर विराम लग सकेगा।

धर्मांतरण पर गांधीजी के बयान और सुप्रीम कोर्ट का फरमान

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं की धर्मान्तरणकारी गतिविधियों पर चिन्ता जताते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और केन्द्र सरकार को इसकी रोकथाम के बावत सख्त कदम उठाने का फरमान जारी किया है। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसी चिन्ता जतायी है जिसमें कहा गया है कि विदेशी धन से संचालित रिलीजियस मजहबी संस्थाओं द्वारा देश भर में भोले-भाले लोगों को लोभ-लालच-प्रलोभन दे कर अथवा भयभीत कर जबरिया धर्मांतरित कर देने का धंधा व्यापक पैमाने पर चल रहा है, जिससे व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि देश का कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने के लिए तो स्वतंत्र है ; किन्तु धर्मांतरण्कारी संस्थाओं द्वारा धोखाधडी-लोभ-लालच-भय-प्रलोभन आदि हथकण्डों के सहारे किया जाने वाला सुनियोजित धर्मांतरण एक गम्भीर मामला है, क्योंकि इससे व्यक्ति की अन्तरात्मा प्रभावित होती है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि इस प्रकार के धर्मांतरण से राष्ट्र की एकता-अखण्डता व राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है ;

अतएव इसे रोका जाना अनिवार्य है। जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता व मान्यता भारत के राष्ट्रीय युवा- स्वामी विवेकानन्द और महान स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविन्द के चिन्तन-उद्बोधन पर आधारित है। मालूम हो कि स्वामी विवेकानन्द ने कह रखा है कि ह्लधर्मांतरण एक प्रकार से राष्ट्रान्तरण है। धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति जब रिलीजन व मजहब को अपना लेता है, तब वह प्रकारान्तर से भारत के विरुद्ध हो जाता है ;

क्योंकि धर्म तो भारत की आत्मा है, जबकि रिलीजन व मजहब अभारतीय अवधारणा हैं। इसी तरह से महर्षि अरविन्द का कथन है कि ह्लधर्म (सनातन) ही भारत की राष्ट्रीयता है और धर्मांतरण से भारतीय राष्ट्रीयता क क्षरण अवश्यम्भावी है। भारत के इतिहास और भूगोल में यह तथ्य सत्य सिद्ध हो चुका है। भारत-विभाजन अर्थात पाकिस्तान-सृजन और खण्डित भारत के भीतर यत्र-तत्र रिलीजियस-मजहबी जनसंख्या के बढते आकार से उत्पन्न विभाजनकारी

पृथकतावादी आन्दोलन इसके प्रमाण हैं। सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी भी धर्मांतरण का मुखर विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहां तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मांतरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन मिशन्स- देयर प्लेस इन इण्डिया नामक पुस्तक के टॉक विथ मिशनरिज अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि ह्लभारत में

आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना तथा उनका युरोपीकरण करना है। आगे वे कहते हैं- ह्लभारत में ईसाइयत अराष्ट्रीयता एवं युरोपीकरण का पर्याय हो चुकी है। चर्च-मिशनरियां धर्मांतरण का जो काम करती रही हैं उन कामों के लिए स्वतंत्र भारत में उन्हें कोई भी स्थान एवं अवसर नहीं दिया जाएगा ; क्योंकि वे समस्त भरतवर्ष को नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ऐसी किसी चीज का होना एक त्रासदी है। सन 1935 में चर्च-मिशन की एक नर्स ने महात्मा गांधी से हुई एक भेंटवार्ता में जब यह पुछा था कि ह्लक्या आप कन्वर्जन (धर्मांतरण) के लिए मिशनरियों के भारत-अगमन पर रोक लगा देना चाहते हैं ? तब गांधीजी ने जो उत्तर दिया था सो सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता के परिप्रेक्ष्य में आज भी प्रासंगिक है- गांधीजी ने कहा था झ्र ह्लअगर सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं कानून बना सकूं तो मैं धर्मांतरण का यह सारा धंधा ही बन्द करा दुंगा।(सम्पूर्ण गांधी वांग्मय- खण्ड 61) बावजूद इसके आज देश भर में ऐसी रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, जो शिक्षा-स्वास्थ्य-सेवा के विविध प्रकल्पों और सामाजिक न्याय व समता-स्वतंत्रता के विविध

आकर्षक सब्जबागों एवं विकास-परियोजनाओं की ओट में देसी-विदेशी धन के सहारे छलपूर्वक धर्मांतरण का धंधा संचालित कर रही हैं । इन संस्थाओं की कारगुजारियों के कारण यहां कभी असहिष्णुता का ग्राफ ऊपर की ओर उठ जाता है , तो कभी दलितों की सुरक्षा का ग्राफ नीचे की ओर गिरा हुआ बताया जाता है । ये संस्थायें भिन्न-भिन्न प्रकृति और प्रवृति की हैं । कुछ शैक्षणिक-अकादमिक हैं , जो शिक्षण-अध्ययन के नाम पर भारत के विभिन्न मुद्दों पर तरह-तरह का शोध-अनुसंधान करती रहती हैं ;

तो कुछ संस्थायें ऐसी हैं , जो इन कार्यों के लिए अनेकानेक संस्थायें खडी कर उन्हें साध्य व साधन मुहैय्या करती-कराती हुई विश्व-स्तर पर उनकी नेटवर्किंग भी करती हैं । डी०एफ०एन० (दलित फ्रीडम नेटवर्क) संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी संस्था है , जो भारत में दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें भडकाने के लिए विभिन्न भारतीय-अभारतीय संस्थानों का वित्त-पोषण और नीति-निर्धारण करती है । इसके प्रमुख कर्त्ता-धर्ता डॉ० जोजेफ डिसुजा नामक अंग्रेज हैं, जो ए०आई०सी०सी०(आल इण्डिया क्रिश्चियन काउंसिल) के भी प्रमुख हैं । डी०एन०एफ० के लोग खुद को भारतीय दलितों की मुक्ति का अगुवा होने का दावा करते हैं ।

वस्तुतः धर्मान्तरण और विभाजन ही डी०एफ०एन० की दलित-मुक्ति परियोजना का गुप्त एजेण्डा है , जिसके लिए यह संस्था भारत में दलितों के उत्पीडन की इक्की-दुक्की घटनाओं को भी बढा-चढा कर दुनिया भर में प्रचारित करती है , तथा दलितों को सवर्णों के विरूद्ध विभाजन की हद तक भडकाने के निमित्त विविध विषयक उत्पीडन साहित्य के प्रकाशन-वितरण व तत्सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती-कराती है । डी०एफ०एन० का नियमित पाक्षिक प्रकाशन- दलित वायस भारत में पाकिस्तान की तर्ज पर एक पृथक दलितस्तान राज्य की वकालत करता रहता है । डी०एफ०एन० को अमेरिकी सरकार का ऐसा वर-दहस्त प्राप्त है कि वह अमेरिका-स्थित दलित-विषयक विभिन्न सरकारी आयोगों के समक्ष भारत से दलित आन्दोलनकारियों को ले जा झ ले जा कर भारत-सरकार के विरूद्ध गवाहियां भी दिलाता है । डी०एफ०एन० दलितों को भडकाने वाली राजनीति के लिए ही नहीं , बल्कि भारत के बहुसंख्य समाज के विरूद्ध दलित-उत्पीडन और उसके निवारणार्थ विभाजन की वकालत-विषयक शोध-अनुसंधान के लिए भी शिक्षार्थियों व शिक्षाविदों को फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करता है । इसने कांचा इलाइया नामक उस तथाकथित भारतीय दलित चिंतक को उसकी पुस्तक- ई आई एम नॉट ए हिन्दू के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान किया है , जिसमें अनुसूचित जातियों-जनजातियों-ईसाइयों और पिछडी जाति के लोगों को सवर्णों के विरूद्ध सशस्त्र युद्ध के लिए भडकाया गया है ।

पी०आई०एफ०आर०ए०एस०(पॉलिसी इंस्टिच्युट फॉर रिलीजन एण्ड स्टेट) अर्थात पिफ्रास अमेरिका की एक ऐसी संस्था है , जिसका चेहरा तो समाज और राज्य के मानवतावादी लोकतान्त्रिक आधार के अनुकूल नीति-निर्धारण को प्रोत्साहित करने वाला है , किन्तु इसकी खोपडी में भारत की वैविध्यतापूर्ण एकता को खण्डित करने और हिन्दुओं (दलितों) के धर्मान्तरण की योजनायें घूमती रहती हैं । इन धर्मान्तरणकारी मिशनरी संस्थाओं का एक वैश्विक गठबन्धन भी है, जिसका नाम- एफ०आई०ए०के०ओ०एन०ए० (द फेडरेशन आफ इण्डियन अमेरिकन क्रिश्चियन आर्गनाइजेसंस आफ नार्थ अमेरिका) अर्थात फियाकोना है । ये दोनो संगठन एक ओर विश्व-मंच पर भारत को मुस्लिम-ईसाई अल्पसंख्यकों का उत्पीडक देश के रुप में घेरने की साजिशें रचते रहते हैं, तो दूसरी ओर भारत के भीतर नस्लीय भेद एवं सामाजिक फुट पैदा करने के लिए विभिन्न तरह के हथकण्डे अपनाते रहते हैं ।

इसी तरह से डी०एफ०एन० जहां भारत के भीतर बहुसंख्यक समाज के विरूद्ध दलितों और अल्पसंख्यकों को भडका कर धर्मांतरण के सहारे विखण्डन की दरार को चौडा करने में लगी हुई है , वहीं भारत के बाहर वैश्विक मंचों पर भारतीय राज्य-व्यवस्था को अक्षम-अयोग्य व हिन्दूवादी होने का दुष्प्रचार कर इस देश में अमेरिकी हस्तक्षेप का वातवरण तैयार करने में भी सक्रिय है । ऐसे में भारत की सम्प्रभुता व अखण्डता की सुरक्षा के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने के बावत सरकार को निर्देशित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की चिन्ता वाजीब है । उसे तो इन विखण्डणकारी विदेशी संस्थाओं के देसी कारिन्दों के विरुद्ध भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ।

धार्मिक शिक्षा के कारण शक्तिशाली बना कायर व कायर बना शक्तिशाली

अभी तक चीरहरण होने वाली न द्रोपदीयो की संख्या रुकी, न चीरहरण करने विधर्मियो वालो की , संख्या रुकी तो सिर्फ रक्षा करने वाले गोविंदा की । क्योंकि सनातनियो को कायर बनाने के षड्यंत्र के चलते सर्वश्रेष्ठ धर्मयोद्धा योगिराज श्री कृष्ण भगवान के योध्य स्वरूप को रसिक रूप में परिवर्तित करने वाली विधर्मी नीति का अनुशरण कर आज सनातनी धर्म गुरु स्वम धन , वैभव , परस्त्री गमन व वासना की लिप्सा से ग्रसित हैं। जिस कारण सनातनियो को शौर्यता व पराक्रम करने हेतु उचित मार्गदर्शन ही प्राप्त नहीं है, अन्यथा क्या कारण रहा होगा की जिन कायर व अकर्मण्य हिन्दुओ ने भय , लालच व मृत्यु के डर से कुछ वर्ष पूर्व इस्लाम को स्वीकार किया था आज वही परिवर्तित रक्त की संताने उन सनातनियो को भयभीत करने में सफल हो रही हैं जिनके पूर्वजो ने शौर्यता का परिचय देकर इस सनातनी पीढ़ी को स्वधर्म में जीवन व्यापन करने का गौरवपूर्ण अवसर दिया था । विधर्मियो के विरुद्ध हिंसा करके मानवता की रक्षा करना ही मात्र एक धर्म है ऐसा कहने वाले भगवान नारायण द्वारा रचित श्री भगवद गीता के ज्ञान को सनातनी हिन्दुओ तक पहुंचाने में सनातनी धर्म गुरु व धर्म प्राचरक पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए इसको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए । जबकि अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर एक मजहबी व्यक्ति ने ऐसी मानसिकता को स्थापित किया जिसको पढ़कर,समझकर या सुनकर, शिक्षित हो या अशिक्षित व्यक्ति , मजहब के प्रति इतना कटटर बन जाता है जिसके कारण श्रद्धा को पैतीस टुकड़ो में काटने वाले आफताब जैसे नरपिशाचों को यह कुकर्म भी इतना पाक नजर आता है जिसके चलते उसे मौत की सजा का भी भय नहीं क्योंकि ऊपर उसका इंतजार ७२ हूरें कर रही है । अब ऐसी मजहबी शिक्षा को दोषी न मानकर आफताब को, जो वामपंथी लोग मानसिक बीमार कह रहे हैं वास्तव में वो स्वम मानसिक दिवालिया हो चुके हैं । क्योंकि ७२ हूरों की प्राप्ति व काफिरो की हत्या का लक्ष्य एक आफताब का नहीं अपितु पूरी मजहबी कौम का है । यदि अति शीघ्र ऐसी कट्टरपंथी शिक्षा पर सार्वजनिक रूप से विधि पूर्वक चर्चा नहीं हुई तो यह असफलता भारत की पूरी न्यायिक प्रणाली व व्यवस्था की होगी ।

जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को किया मजबूर

भारतीय सैनिकों की वीरता की गाथाओं से हम परिचित हैं। आज जब भारत की सीमाओं पर शत्रु देश अवसर की ताक में है, तब हमारी सेनाएं अत्यंत चौकन्ना हैं और उसी वजह से हम सुरक्षित हैं और हमारा देश भी सुरक्षित है। आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के सैन्य शक्ति के उस शौर्य की, जिसमें 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों को घुटने टेके पर मजबूर कर दिया।

आज हमारा देश ढाका विजय दिवस की 50वीं सालगिरह को एक यादगार के रूप में मना रहा है। यह दिवस आज इसलिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि इस वर्ष भारत देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। दुनियां में एकमात्र इस सीधी लड़ाई 1971 में बांग्लादेश की आजादी को लेकर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई। इस सीधी लड़ाई में भारतीय सेना के नायक जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल नियाजी ने अपने 93 हजार सैनिकों के साथ आत्म समर्पण किया था।

1969 में सेना प्रमुख सैम हॉरमुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ ने जेएफआर जैकब को पूर्वी कमान प्रमुख बना दिया था। जैकब ने 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मनों को रणनीतिक मात दी थी। जैकब के मुताबिक 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। बेहतर जिन्दगी की तलाश में बांग्लादेश के शरणार्थी लाखों की संख्या में सीमा पार करके देश के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में लोग इस्लामी कानूनों के लागू होने और उर्दू को बतौर राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। इसलिए हालात ज्यादा खतरनाक हो गए थे। पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने वाले जनरल रिटायर्ड जैकब फर्ज रफेल जेएफआर जैकब के मुताबिक भारत के तीखे हमलों से परेशान होकर पाकिस्तान सेना ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में युद्ध विराम की पेशकश की जिसे भारतीय सेना ने अपनी चतुराई और पराक्रम से पाकिस्तान के पूर्वी कमान के 93000 सैनिकों के सरेंडर में बदल दिया।

नियाजी के पास ढाका में ही करीब 30 हजार सैनिक थे जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग तीन हजार रही। जैकब के मुताबिक उसके पास कई हफ्तों तक लड़ाई लड़ने की क्षमता थी। अगर नियाजी ने समर्पण करने की बजाय युद्ध लड़ता तो पोलिश रिजॉल्यूशन जिस पर संयुक्त राष्ट्र में बहस हो रही थी वह लागू हो जाता और बांग्लादेश की आजादी का सपना अधूरा रह जाता। लेकिन वह समर्पण के लिए

तैयार हो गया। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने में सबसे अहम भूमिका मुक्ति वाहिनी की रही। मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में पूर्वी पाकिस्तान से लगातार आ रहे शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को मजबूत करने का निर्णय लिया। इस फैसले के तहत मुक्ति वाहिनी को हथियार दिए गए।

इसके साथ ही युद्ध खत्म हो गया और बांग्लादेश का उदय हुआ। हार से तिलमिलाए नियाजी ने कहा जैकब ने मुझे ब्लैकमेल किया, हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों बाद चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान को युद्ध जांच आयोग का प्रमुख बनाकर हार की वजह का पता लगाने का काम सौंपा गया। कमीशन ने जनरल नियाजी को तलब कर पूछा कि जब ढाका में उनके पास 26400 जवान थे, तब उन्होंने ऐसे शर्मनाक तरीके से क्यों समर्पण किया जबकि वहां पर सिर्फ कुछ हजार ही भारतीय फौज थी। जनरल नियाजी ने जवाब दिया, मुझे ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा।

जेएफआर जैकब के मुताबिक 1971 की लड़ाई में पश्चिमी मोर्चे पर रक्षात्मक, आक्रामक और पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की बेहद आक्रामक रणनीति बनी थी। बारिश रुकने तक बांग्लादेश पर हमला न करने की बात जनरल जैकब ने कही थी। इस बीच जनरल ने युद्ध की सारी तैयारियां पूरी कर लीं। और जब युद्ध शुरू हुआ तो जनरल जैकब ने खुलना और चटगांव पर हमला बोलने के आदेश को नजर अंदाज करते हुए ढाका पर फोकस करना उचित समझा। जैकब जब ढाका के पास पहुंचे तो उनके पास 3 हजार जवानों की फौज थी जबकि नियाजी के पास करीब 30 हजार फौजी थे। लेकिन नियाजी जानता था कि बंगाली लोग उसके खिलाफ हैं। नियाजी ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत युद्ध विराम समझौता करने की पेशकश कर दी। 16 दिसंबर को जैकब बिल्कुल निहत्थे हाथों में सिर्फ सरेंडर के कागज लेकर नियाजी के मुख्यालय पहुंच गए। समर्पण के कागज जैकब ने खुद ड्राफ्ट किए थे, लेकिन इस पर आलाकमान से मंजूरी नहीं मिली थी। इस बीच राजधानी में मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तानी सेना के बीच युद्ध जारी था।

भारत की ओर से पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे जेएफआर जैकब ने नियाजी से कहा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर जनता के बीच आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो हम आपकी और आपके फौजियों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूं। अगर तुम कोई फैसला नहीं कर पाए तो मैं हमले का आदेश दे दूंगा। बाद में नियाजी के दफ्तर से जैकब लौट आए। उस समय की घटना के संबंध में जैकब बताते है कि वे नियाजी के पास दोबारा पहुंचे और उन्होंने मेज पर समर्पण के कागजात रखे हुए थे। मैंने पूछा जनरल क्या आप इसे मंजूर करते हैं मैंने नियाजी से तीन बार पूछा। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने समर्पण कर दिया। 1971की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना भारतीय फौजों के सामने सिर्फ 13 दिन ही टिक सकी। इतिहास की सबसे कम दिनों तक चलने वाली लड़ाइयों में से एक इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के करीब 93 हजार सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आधुनिक सैन्य काल में इस पैमाने पर किसी फौज के आत्मसमर्पण का यह पहला मामला था।

जागरूकता ही कैंसर की गंभीरता से बचाता है

कोरोना महामारी के प्रकोप को कंट्रोल करने के बाद से सरकार ने एक बार फिर से उन बीमारियों को काबू करने की तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया है जो देश की एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है. इन बीमारियों में कैंसर प्रमुख है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआईआर) की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में लगभग 16 लाख कैंसर के मरीज हैं. 2025 तक यह आंकड़ा 12 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है. हालांकि समय रहते इसका इलाज संभव है. लेकिन जरा सी लापरवाही और जागरूकता की कमी पर यह इंसान को मौत के मुंह में धकेल देता है.

लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से देश में हर वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है ताकि इसके उपचार और लक्षणों के प्रति लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके. हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 04 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी के जन्मदिन 07 नवंबर को मनाया जाता है. जिसे 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा घोषित किया गया था.

वर्ष 2022-2024 में कैंसर का थीम ह्लउ'ङ्गरी श्रै उंश्री ऋ्रत्रह्व रखा गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है. 2018 में विश्व स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले कैंसर से संबंधित थे. साल 2040 तक यह मामले दोगुने होने का अनुमान लगाया जा रहा है. जो इसकी गंभीरता को दशार्ता है. भारत में हर साल 7 नवंबर को लोगों को मुफ्त कैंसर जांच के लिए केंद्र से लेकर नगरपालिका के अस्पतालों तक जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वहां पहुंचकर अपनी प्रारंभिक जांच करा सकें. जिससे उन्हें यह पता लग सके कि उन्हें किसी प्रकार की कोई कैंसर की कोई शिकायत तो नहीं है. अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी तुरंत जांच कराने की सलाह दी जाती है, ताकि रोगी का जल्द से जल्द उपचार कर उसे रोगमुक्त बनाया जा सके. दरअसल कैंसर बीमारियों का वह एक समूह है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं तथा शरीर में अपने आसपास के हिस्से पर आक्रमण करने या अन्य अंगों में फैलने के लिए अपने सामान्य सीमाओं को पार कर जाती है. यह शरीर के किसी भी अंग में शुरू हो सकती है. फेफड़े, प्रोस्टेट, पेट एवं

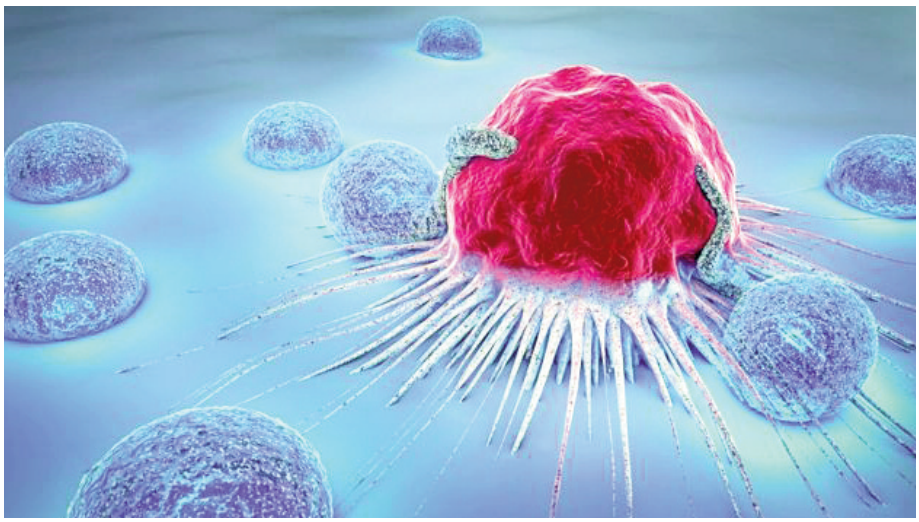

यकृत का कैंसर पुरुषों में सबसे आम है जबकि स्तन या थायराइड का कैंसर महिलाओं में सबसे आम है. सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराने वाली एक संस्था दृष्टि के शोध के अनुसार मुख्य कैंसर के रोगियों को छोड़कर 30 से 50 प्रतिशत रोगियों को कैंसर में शुरूआती लक्षणों की जांच कर ठीक किया जा सकता है.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िलों में भी कैंसर रोगियों की संख्या देखी जा सकती है. हालांकि समय समय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा जांच शिविर लगाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता रहता है. कुछ माह पहले जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के आयुक्त कार्यालय में कैंसर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था. इसका उद्देश्य आशा वर्करों को कैंसर से जुड़े लक्षणों से परिचित कराना था, ताकि वह ग्रामीण स्तर पर महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की पहचान कर उस महिला को इलाज के लिए प्रेरित कर सकें. अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर महिलाएं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं जब तक वह बहुत अधिक बीमार ना हो जाएं क्योंकि गांव में वह अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि वह अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं. जिसके कारण बाद में वह गंभीर रोग बन जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है.

द हिंदू समाचारपत्र की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से कठुआ जिले में टाटा मेमोरियल कैंसर संस्था की शाखा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर भटकना न पड़े. अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक इस हॉस्पिटल को तैयार करती है ताकि इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को कैंसर के प्रति एक बेहतर इलाज मिल सके. क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कैंसर के मरीजों की गिनती कुछ काम नहीं है. 2018 से 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार 21 हजार से अधिक लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई है. यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है. हालांकि सरकार की ओर से कैंसर पीड़ित के बेहतर इलाज के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें देश के किसी भी कैंसर संस्थान में इलाज के लिए मुफ्त रेल यात्रा भी शामिल है. इसके अतिरिक्त आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत भी कैंसर पीड़ित को इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है. लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग इन योजनाओं का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं.

कैंसर से अपने परिजन को खो चुके जम्मू के सीमावर्ती गांव पुंछ के एक परिवार का कहना था कि उनके मरीज पिछले कई वर्षों से ब्लैडर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. उनका बहुत इलाज करवाया गया. इस दौरान काफी पैसे भी खर्च हुए, आयुष्मान स्कीम के तहत पांच लाख मदद भी मिली, लेकिन शुरूआत में इस बीमारी को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेने और उचित इलाज नहीं कराने का परिणाम उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. चार वर्ष पूर्व कैंसर के कारण अपने पिता को खो चुके डीडी न्यूज दिल्ली में कार्यरत शम्स तमन्ना कहते हैं कि शुरूआत में कई लक्षणों को सामान्य बीमारी समझ कर नजरअंदाज करना ही उनके पिता की मृत्यु का कारण बना था. जब तक वह इसकी गंभीरता के प्रति सचेत होते तब तक वह अंतिम स्टेज पर पहुंच चुका था.

शनि की वापसी- दोहरी सेंचुरी - नरेन्द्र मोदी - 2023

शनि एक राशि में लगभग अढ़ाई साल रहते हैं और बारह राशियों में गोचर करने में शनि को लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। जन्मकुंडली में स्थिति शनि पर शनि का दोबारा गोचर लगभग 27 से 30 वर्ष की अवधि में होता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने करियर में लगभग स्थापित हो चुका होता है या फिर स्थापित होने का प्रयास कर रहा होता है। इससे पूर्व के जीवन में व्यक्ति ने शिक्षा अर्जित कर जो भी योग्यता पाई है उसे प्रयोग करने का यह समय होता है।

शनि को एक ही स्थान पर वापस आने में लगभग 29 वर्ष लगते हैं और उस वर्ष को शनि की वापसी कहते हैं। शनि की यह वापसी व्यक्ति को दुनिया को समझने, जानने और विश्लेषण करने के अवसर देती है। जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम जीवन की एक सीधी राह में चले जा रहे होते हैं कि तभी किसी चौराहे पर आकर हमें यह निश्चित करना होता है कि अब हमें किस ओर जाना है, कौन-सी राह पकड़ने पर हम अपने जीवन लक्ष्य को पा सकेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

भारतीय राजनीति को एक नया आयाम देने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के 27 से 30 वर्ष के मध्य का समय अति महत्वपूर्ण था। इस समय के दौरान अटल जी 1954 में बलरामपुर से सांसद चुने गए। मात्र इस छोटी सी आयु में यह पद पाना किसी के लिए भी सम्मान और गौरव का विषय रहेगा। इस पद के साथ ही अटल जी सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए। इनकी कुंडली में शनि द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में है एवं तृतीयेश व चतुर्थेश है। इस समय इनकी शनि की साढ़ेसाती भी शुरू हुई जो इनके लिए शुभ और उन्नतिकारक साबित हुई। जन्मकुंडली में दशा भी शुक्र में शनि की प्रभावी थी। इनके जीवन की इस समयावधि को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी कहा जा सकता है। शनि साढ़ेसाती की इस अवधि ने उनके जीवन को एक दिशा दी और आगे जाकर अटल जी भारतीय राजनीति का आधार बन पाए।

श्री गुलजारी लाल नंदा

गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन को दिशा देने का कार्य 1927 में हुआ जब जन्म शनि पर गोचर शनि का विचरण हुआ। गुलजारी लाल नंदा जी की कुंडली मेष लग्न और धनु राशि की है। शनि इनके अष्टम भाव में स्थित है। वृश्चिक राशि में स्थित शनि पर 1925 से 1926 के मध्य रहा। यह समय इन्हें राजनीति जीवन में लेकर आया।

श्रीमती इंदिरा गांधी

शनि 1945 से 1946 की अवधि में शनि इनकी

जन्म राशि पर गोचर कर रहे थे। उस समय इनके जीवन में बदलाव हुआ और इंदिरा गांधी ने पारिवारिक जीवन में माता की भूमिका की शुरूआत की। इसके बाद जब शनि दोबारा 1975 में इनके जन्म शनि पर गोचरवश आए तो इन्होंने देश में आपातकाल लागू किया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने यह कदम उठाया जो जीवन के अंत तक इनके लिए आलोचना का कारण बना। 1984 में इनकी मृत्यु के समय शनि इनके चतुर्थ भाव पर गोचर कर, लग्न में स्थित जन्म शनि को प्रभावित कर रहा था जो इनकी मृत्यु की वजह बना।

जवाहरलाल नेहरू

जवाहर लाल नेहरू जी के जीवन का 1918-1919 वर्ष की अवधि का समय राजनीतिक जीवन में प्रवेश का समय कहा जा सकता है। जवाहर लाल नेहरू इस समय महात्मा गांधी के संपर्क में आए और इन्होंने राजनीतिक जीवन की इनसे इस समय में दीक्षा ली। यह वह समय था जब इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिल कर रॉलेट रॉलेट अधिनियम ने खिलाफ आंदोलन किया। इस समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसके बाद 1947 से 1948 की अवधि का समय इनके जीवन का सबसे खास समय था क्योंकि इसी दौरान वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तत्पश्चात शनि जब इनके जन्म शनि से गोचर में सप्तम भाव में आए और जन्म शनि को गोचर में सक्रिय किया तो वह इनके परलोक गमन का समय था। यह वर्ष था 1964 का। इनकी जन्मकुंडली कर्क लग्न और कर्क राशि की है। शनि इनकी कुंडली में सिंह राशि में स्थित है। जीवन में शनि भी इनके जन्म शनि से गुजरे, इनका जीवन बदल गया।

नरेन्द्र मोदी - 2023

अब बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी की। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। शनि इनके दशम भाव में सिंह राशि में स्थित हैं। इनका जन्म 1950 में हुआ और शनि इन पर 1977 में आए। उस समय नरेंद्र मोदी आर।एस।एस। में महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आए। इसके बाद 2022 से 2023 के मध्य शनि जन्म शनि से सप्तम भाव पर गोचर करेंगे।

यह बात आज किसी से छुपी नहीं हैं-दुनियाभर में फैले आतंकवादियों के मन में नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी शासन के विरुद्ध घृणा दिनप्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसका प्रभाव आगे क्या रहेगा, ज्योतिष के माध्यम से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। नरेन्द्र मोदी की जन्म पत्रिका की सबसे बड़ी खासियत केन्द्र स्थानों में पाँच ग्रहों का उपस्थित होना है। इससे भी बड़ा एक राजयोग है जिसमें चन्द्रमा से केन्द्र में स्थित बृहस्पति से बन रहे गजकेसरी योग को चन्द्रमा से ही केन्द्र में बैठे शुक्र का सहयोग मिल रहा है। चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति को दशम भाव में बैठे शुक्र दृष्टिपात कर रहे हैं, बल्कि दोनों ही ग्रह एक-दूसरे पर दृष्टिपात करके इस योग को कई गुना अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी की जगत ख्याति का रहस्य उनके जिस योग में छिपा हुआ है, वह यह है कि लग्न में स्थित मंगल चतुर्थ भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। उधर चतुर्थ भाव के स्वामी शनि चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं।

याद रहे दशम भाव में स्थित शनि व्यक्ति को थोड़ा सा डिक्टेटर बनाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, मार्टिन लूथर किंग, शेख मुजीबुर्र रहमान आदि के दशम भाव में शनि थे। ये सब इतिहास बनाने में सफल हुए। क्या नरेन्द्र मोदी की कुण्डली में ऐसा है?

अनुमान है कि देश के बाहर के कुछ संगठन व देश के अन्दर ही कुछ लोग नरेन्द्र मोदी की जान के लिए खतरा हैं। आप गौर करें कि जो लोग भारत में शासन के दावेदार रहे हैं, उनके आसपास के या विश्वसनीय कुछ लोगों की मृत्यु स्वाभाविक ढ़ंग से नहीं हुई है। जनता में अफवाहें भी रही हैं। सत्ता के लिए संघर्ष न केवल खिलजियों, मुगलों, तुर्क व मंगोलों में रहे हैं बल्कि सम्राट अशोक के बारे में भी यह कथन है कि सम्बन्धियों के बहुत बड़े रक्तपात के बाद वे शासन में आये थे। सत्ता का चरित्र ही यही है। सत्तासीन लोगों को हटाये बिना शासन प्राप्ति संभव नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से व तानाशाही में बल प्रयोग या रक्तपात के माध्यम से ऐसी कोशिशंग सदा ही हुई है। परन्तु नरेन्द्र मोदी की कुण्डली में मध्यम आयु के योग हैं।

नरेन्द्र मोदी का आयु योग

जैमिनी ऋषि ने आयु गणना के जो तीन आयाम

बनाये हैं, उनमें वे एक ऐसे योग का लाभ पा रहे हैं जो अपवाद स्वरूप है। ह्यपितृलाभगे चन्द्रे, चन्द्र मन्दाभ्याम्ह्ल अगर लग्न या सप्तम भाव में चन्द्रमा हों तो चन्द्रमा और शनि की स्थिति से ही आयु निर्धारण करना चाहिए। उनके चन्द्रमा स्थिर राशि में हैं और शनि भी स्थिर राशि में हैं। दोनों स्थिर राशि में होने से उनको मध्यायु का योग बना है, जिसकी ऊपरी सीमा 80 वर्ष है। अगर केन्द्र में बृहस्पति हों तो कुछ आयु और भी बढ़ जाती है। शनि पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण कक्षा हानि भी नहीं होगी। अर्थात मध्यायु योग बना रहेगा। किसी कारण से कक्षा हानि होती भी है तो एक अन्य योग उपलब्ध है- ह्यरोगेशे तुंगे नवांश वृद्धिःह्ल अर्थात अष्टमेश यदि उच्च राशि में हो तो नौ वर्ष आयु और मिल जाती है। लग्न में अपनी ही राशि में बैठे मंगल आयु योग को पुष्ट करते हैं। इनके आत्मकारक शनि से त्रिकोण स्थान शुद्ध है और आयु हानि नहीं करते हैं। इन सब बातों से नरेन्द्र मोदी मध्यायु योग के ठहरते हैं जिसकी औसत गणना 80 वर्ष की है।

क्या उनकी मारक दशाएँ चल रही हैं?

नहीं, वे इस समय मंगल महादशा की राहु अन्तर्दशा में चल रहे हैं, जो कि मई 2023 तक रहेगी। उसके बाद गुरु अन्तर्दशा रहेगी जो कि अप्रैल 2024 तक रहेगी और उसके बाद मंगल महादशा की शनि अन्तर्दशा रहेगी जो कि अप्रैल 2024 से मई 2025 तक रहेगी। जनवरी, 2023 से मार्च, 2025 तक शनिदेव कुम्भ राशि में रहेंगे और इस समय वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चतुर्थ भाव में भ्रमण करते हुए उनकी लग्न पर दृष्टिपात करेंगे। शनि की लग्न पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। इस अवधि में ही वे दो बार वक्री भी होंगे, 18 जून, 2023 से कुछ महीनों के लिए तथा जून, 2024 से कुछ महीनों के लिए। राशि कुम्भ ही रहेगी। परन्तु उनको प्रथम तो बृहस्पति ही मीन राशि में रहते हुए लग्न पर दृष्टिपात करेंगे और अप्रैल 2023 तक सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे जो पुनः आयु रक्षा करेंगे। मई 2023 से अप्रैल, 2024 तक बृहस्पति की अन्तर्दशा है और जब पुनः शनि की अन्तर्दशा आएगी तब उनके बृहस्पति वृषभ राशि में रहते हुए एक वर्ष तक लग्न पर दृष्टिपात करेंगे। इसका मतलब आयु को खतरा नहीं है। आतंकवादी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बल्कि कुम्भ राशि के शनि शत्रुहंता योग बना रहे हैं और उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा देंगे।

किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह

एक प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध राजनेता रहे चौधरी चरण सिंह अपनी वाक पटुता और दृढविश्वासपूर्ण साहस के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में लिखने के दो मूल कारण हैं- पहला तथ्य यह है कि मैं किसान समुदाय की पृष्ठभूमि से हूं और दूसरा मैं उस वंश समानता की अवधारणा और भाईचारे की भावना से अवगत हूँ जोकि पूरे भारत में विशेष रूप से जाट समाज में पायी जाती है। मैं मिट्टी का पुत्र हूं और मैं मिट्टी के एक और पराक्रमी बेटे से बहुत निकटता से जुड़ा हूँ। उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व किया। चौधरी चरण सिंह देश के अंतिम महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे जिनका सक्रिय राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता पूर्व राजनीतिक आंदोलनों से लेकर स्वतंत्रता के बाद की पार्टी राजनीति तक फैला था। उनकी राजनीतिक यात्रा में जिला, राज्य और राष्ट्रीय राजनीति शामिल थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आम आदमी के कल्याण के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की शुरूआत करने का प्रयास किया। उन्होंने श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में उपप्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह भारतीय क्रांति दल और लोक दल के संस्थापक थे।

चौधरी चरण सिंह को इतिहासकारों और सामान्य लोगों द्वारा किसानों के मसीहा के रूप में सम्मान दिया जाता है। इसलिए यह शीर्षक उनके लिए पूरी तरह से उपयुक्त प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश के कृषक जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चरण सिंह ने देश के किसानों और कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू के दिनों में अपने लोगों के लिए जोरदार तरीके से लड़े थे। उन्हें नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 64 वे सत्र में भूमि नीतियों के खिलाफ बोलते हुए भी देखा गया था।

पॉल ब्रास ने अपने लेख ह्लचौधरी चरण सिंहः एक भारतीय राजनीतिक जीवनह्व, जो उन्होंने इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, दिनांक 25,ङ्क.1993 ((पीपी 2087-2088) में प्रकाशित किया था, लिखते हैं कि ह्लचरण सिंह खतरों से दृढता से निपटने के इच्छुक थे। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उनके दो कार्यकाल में सार्वजनिक व्यवस्था स्पष्ट थीह्व। अपने विचारों को दोहराते हुए पॉल ब्रास ने उसी लेख में लिखा है कि उनकी प्रतिक्रिया सार्वजनिक व्यवस्था और विपक्षी ताकतों की राजनीतिक गतिविधियों के विघटन को रोकने के लिए किए गए उपायों पर केंद्रित थी ; कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले हडपने के आंदोलन से उनका दृढ संचालन; विश्वविद्यालय छात्र संघ में अनिवार्य सदस्यता पर प्रतिबंध; उनके कार्यकाल के दौरान छात्रों की हड़ताल की सापेक्ष अनुपस्थिति; और

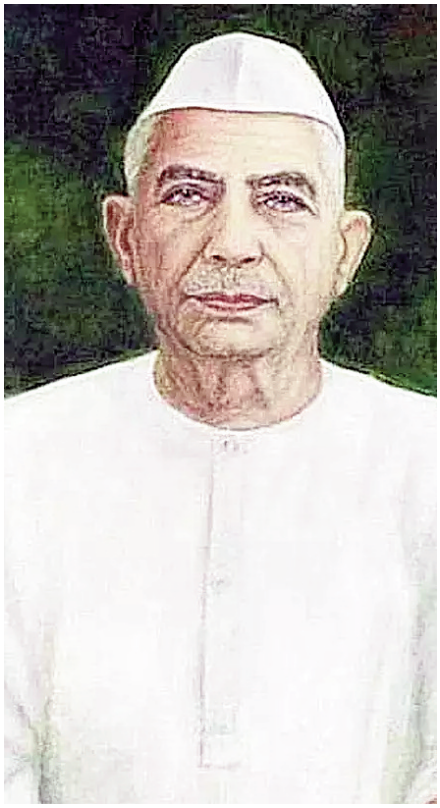

जो एक बड़ी हड़ताल हुई थी, उसे तोड़नाह्व इन उपायों ने चरण सिंह की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए राजकोष की वित्तीय अखंडता के लिए चिंताओं को चित्रित किया। चौधरी चरण सिंह को उनकी दूरदृष्टि और भारत के विकास की योजना के लिए जाना जाता है जिससे उन्होंने गांवों और ग्रामीण भारत के लिए बात की थी। गाँव हमेशा से भारतीय समाज के सूक्ष्म रूप रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने 1947 में ह्लएबोलिशन ऑफ जमींदारीह्व किताब लिखी और 1956 में उन्होंने राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में खेतिहर कोऑपरेटिव फार्मिंग की रचना की।

संयुक्त खेती, एक्स रे समस्या और उसका समाधान को भारतीय विद्या भवन, बॉम्बे द्वारा 1959 में प्रकाशित किया गया था जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजस्व, सिचाई और बिजली मंत्री के रूप में कार्य किया था। पुस्तक बड़े करीने से एक प्रस्तावना के साथ दो भागों में विभाजित है।भाग 1 में जिसमें दस अध्याय है, पूर्व प्रधानमंत्री ने कृषि संगठन के प्रकार; आधुनिक संयुक्त खेती की विशेषताएं; सहकारी और सामूहिक खेती; हमारी समस्याएं और मूल सीमा; संपदा का सृजन; रोजगार; धन के समान वितरण; लोकतंत्र को सफल बनाना; और बड़े पैमाने पर खेती की अव्यवहारिकता के बारे में चर्चा की। उन्होंने अध्याय ' के तहत विस्तार से बताया कि कैसे एक लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है और अध्याय श के तहत उन समस्याओं और बुनियादी सीमाओं पर चर्चा की जिनका सामना भारत ने किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में जिन मुख्य समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है ये है (१) कुल संपत्ति या उत्पादन में वृद्धि ,(२) बेरोजगारी का उन्मूलन, (३) धन का समान वितरण, और (४५) लोकतंत्र को सफल बनाना (संयुक्त खेती एक्स-रे, 2020 पृष्ठ 25)

उपरोक्त खण्ड के भाग 2 में जो अध्याय कसे शुरू होता है, चरण सिंह उपरोक्त समस्याओं के संभावित समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुस्तक का अगला (बारहवां) अध्याय भूमि सुधार, पुनर्वितरण और उत्प्रवास के मुद्दों पर केंद्रित है जबकि अध्याय क्क्क्क गैर-कृषि व्यवसायों की आवश्यकता के बारे में बात करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के अध्याय श के तहत कंडीशन्सफॉर इंडस्ट्रियलिज्म के मामले को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया है और बताया कि वे भारत में मौजूद नहीं हैं। वह भाग क क के अध्याय श्क में पाठकों को भारत के लिए उपयुक्त औद्योगिक संरचना और अध्याय क के तहत औद्योगीकरण से संभावनाएंह्व के बारे में भी बताते हैं। चरण सिंह मिट्टी के उपयोग; मृदा संरक्षण जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता; और जनसंख्या नियंत्रण के साधन के बारे में अंतिम चार अध्याय (से क्क्क्क) में अपने विचार व्यक्त करते हैं जो पाठक को उन पहलुओं का अहसास कराते हैं जो भारत में सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है और जो उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से उठाई है।

श्री चरण सिंह ने भारत गणराज्य के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री सहित विभिन्न दायित्वों में कार्य किया और एक कठोर कार्यपालक के रूप में ख्याति प्राप्त की। उन्हें प्रशासन में अक्षमता, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं था।

वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने ऋण मोचन विधेयक, 1939 के निर्माण और अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई जिससे ग्रामीण देनदारी को बड़ी राहत मिली। यह भी उनकी पहल पर हुआ कि यू.पी. में मंत्रियों को वेतन और जो अन्य विशेषाधिकार प्राप्त थे उनमें भारी कमी कर दी गई। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भूमि जोत अधिनियम, 1960 को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना था ताकि इसे एक समान बनाया जा सके।

स्वतंत्रता के बाद के भारत के विधायकों का नाम लिया जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से चौधरी चरण सिंह का नाम लूंगा। मैं उन सभी लोगों को भी भारत के पूर्व दूरदर्शी पीएम द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ने के लिए आग्रह करूंगा जो भारतीय राजनीति पर काम कर रहे हैं और ग्रामीण भारत का अध्ययन करना चाहते हैं और जो उनके वैकल्पिक दृश्य को समझने के लिए भारत को विकसित करना चाहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन और शोध के लिए चौधरी चरण सिंह अभिलेखागार एक उपयोगी संस्था हो सकती है। भारत सरकार को इसकी स्थापना के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है।

लैंगिक हिंसा की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम शाला हुआ आयोजन

दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते जिलाधिकारी अंशुल कुमार व अन्य पदाधिकारीगण, स्कूली छात्राओं के बीच जिलाधिकरी.

रजेश पंजिकार (ब्यूरो चीफ)

बांका। बांका के चंद्रशेखर भवन टाउन हॉल में बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा के अवसर पर बांका जिला प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों के बीच जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला का शुभारंभ श्री अंशुल कुमार जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त कार्यक्रम में कौशलेंद्र कुमार,उप विकास आयुक्त, बांका, शालिग्राम साह, वरीय उप समाहर्ता, बांका, वन स्टॉप सेंटर के नोडल पदाधिकारी स्वाति कुमारी, वरीय उप समाहर्ता, बांका एवं परामर्शी अंजना भारती तथा सर्व शिक्षा अभियान के सर्वेश कुमार एवं पीरामल फाउंडेशन के अरविंद कुमार, मासूम रेजा गांधी फेलो आस्था गुप्ता द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया। लैंगिक

हस्ताक्षर प्वाइंट पर हक्ताक्षर करते जिलाधिकारी

हिंसा के विरुद्ध निबंध, पेंटिंग, रंगोली एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत आदि कार्यक्रमों के माध्यम से 300 छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया । जिला पदाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालाः- लैंगिक हिंसा के रोकथाम के लिए हम सभी की पूर्ण भागीदारी एवं सजग होना होगा। अगर किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो वन स्टॉप एवं महिला थाना/महिला हेल्पलाइन के किसी भी महिला अधिकारी से बेझिझक अपनी समस्याओं को रख सकती हैं, जिससे वो तुरंत आपकी सहायता करेंगे। सरकार महिलाओं को 35 % आरक्षण दे रही है और आज महिला हर क्षेत्र में विकास कर रही है तथा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें भी आगे बढ़कर इसका लाभ लेना चाहिए। आप सभी के अन्दर एक प्रतिभा होती है जैसे किसी को पढ़ना नहीं आता है लेकिन खेलना आता है। आप अपनी प्रतिभा को पहचान कर खुद का विकास करें।

लैंगिक हिंसा से संबंधित विद्यालयों में पोस्टर लगाने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया एवं

कार्यक्रम में उपस्थि अतिथिगण, सेल्फी प्वाइंट पर बच्चियों के साथ जिलाधिकारी

बांका जिले में नगर पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित नए चेहरे के सिर पर सज गया ताज

मतगणना केंद्र से विजय प्राप्त कर वापस लौटते वार्ड पार्षदगण।

राजेश पंजिकार

बांका जिले के तीन नगर पंचायत क्षेत्र कटोरिया, बौंसी एवं अमरपुर नगर पंचायत के मतगणना के बाद मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद ,एवं वार्ड पार्षदों के विजय होने की घोषणा के साथ ही जनता ने इस बार नए चेहरे को अपना नेता चुना है। आपको बता दें हैं स्थानीय ढ.इ.र. कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया था . जहां कड़ी सुरक्षा एवं पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था के साथ मतगणना का कार्य सुबह 8:00 बजे से प्रारंभ होने के साथ ही जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने मतगणना केंद्र पहुंचकर विधि व्यवस्था एवं मतगणना कार्यों का जायजा लिया। साथ ही नगर पंचायत अमरपुर के निवार्ची पदाधिकारी डॉ प्रीति , नगर पंचायत बौंसी के निवार्ची पदाधिकारी पारुल प्रिया, एवं नगर पंचायत कटोरिया के निवार्ची पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार से मतगणना संबंधी जानकारी प्राप्त की । मतगणना शुरू होने के थोड़ी देर उपरांत ही वार्ड पार्षदों के विजय की घोषणा का रुझान

उप मुख्य पार्षद बौंसी गुंजन कुमारी

उप मुख्य पार्षद कटोरिया शकीला खातून

मतगणना केंद्र में चाक चौबंद व्यवस्था

आना शुरू हो गया । अंत में कटोरिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में सपना शिवानी 88 मतों से एवं उप मुख्य पार्षद के रूप मेंशकीला खातून 446 मतों से निर्वाचित घोषित हुई ।

अमरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में रीता साहा ने 574 मतों से ,एवं उप मुख्य पार्षद के रूप में आशा देवी ने 2113 मतों से जीत हासिल कर निर्वाचित हुई। बौंसी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में कोमल भारती ने 388 मतों से जीत हासिल कर निर्वाचित घोषित हुई। वही उप मुख्य पार्षद का दिलचस्प मुकाबला रहा जहां 2 प्रत्याशियों गुंजन कुमारी और सोनी कुमारी को समान 3314 मत प्राप्त हुए लॉटरी के द्वारा एक मत अधिक प्राप्त होने से गुंजन कुमारी उप मुख्य पार्षद के रूप में निर्वाचित घोषित हुई।

मुख्य पार्षद अमरपुर रीता साहा

मुख्य पार्षद बौंसी कोमल भारती

मुख्य पार्षद कटोरिया सपना शिवानी

नगर सभापति द्वारा चाय पर चर्चा के दौरान जनसंपर्क अभियान

नगर भ्रमण करते नगर सभापति संतोष कुमार सिंह

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ

बांका। बांका नगर परिषद के सभापति संतोष कुमार सिंह लगातार जनता की समस्याओं से उनके वार्ड में जाकर रूबरू हो रहे हैं आपको बता दूं की बांका नगर परिषद के क्षेत्र के सभी वार्डों में पेयजल की व्यवस्था रोशनी की व्यवस्था एवं सड़क की व्यवस्था दुरुस्त हो इसके लिए नगर परिषद अध्यक्ष स्वयं प्रत्येक वार्डों में घूम घूम कर वार्ड वासियों से उनकी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे त्वरित समाधान हेतु जनता दरबार लगा रहे हैं ताकि आमजन की समस्याओं से अवगत हो सकें। इसी क्रम में चाय पर चर्चा के क्रम में वार्ड नंबर 12 शांति नगर में कमल कुमार घोष के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें सम्मानित बुजुर्गों ,महिलाओं ,एवं युवाओं ने भाग लिया ।बैठक को संबोधित करते हुए नगर सभापति संतोष कुमार सिंह ने बताया मैं वादा नहीं काम पर विश्वास रखता हूं ।

आम जन की कोई भी समस्या का समाधान करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूं और उसका त्वरित निष्पादन करवाता हूं ।आम जनता से अपील है कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं । इसके साथ ही सभापति के द्वारा वार्ड में पेयजल की व्यवस्था ,गली नली की व्यवस्था ,एवं रोशनी की व्यवस्था ,के साथ-साथ सड़कों का भी मुआयना किया। कार्यक्रम में सुप्रकाश सिंह, कमलेश्वरी दास भाजपा युवा नेता रंजीत कुमार, गोपाल सिंह आदि सभी वार्ड वासीमौजूद थे।

सभा को संबोधित करते हुए नगर सभापति संतोष कुमार सिंह

सभा में उपस्थित वार्ड के लोग

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिलाधिकारी अंशुल कुमार हुए सम्मानित

उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के हाथों स्मृति चिन्ह प्राप्त कर हुए सम्मानित

जिलाधिकारी अंसुल कुमार के साथ जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण स्मृति चिन्ह लेते हुए।

राजेश पंजिकार (ब्यूरो चीफ)-

बांका के सदर अस्पताल को मिशन 60 दिन में सबसे बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए जिलाधिकारी अंशुल कुमार को उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सम्मानित किया। मंगलवार को पटना में

आयोजित एक समारोह में जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने डिप्टी सीएम से सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह प्राप्त किया। आपको बता दें कि ,मिशन 60 में सदर अस्पताल की सुविधाओं को तेजी से बढ़ाया गया । इसके अलावा अस्पताल की साफ-सफाई रंग ,रोगन ,लाइटिंग का काम बिना देरी किए 60 दिनों के अंदर पूरा कर लिया गया जिससे बांका सदर अस्पताल बिहार में नंबर वन बन गया है।

सम्मान समहारोह में उपस्थित उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बिहार, सम्मान प्राप्त जिलाधिकारी अंसुल कुमार

मुक्ति निकेतन के संत स्व. अनिरुद्ध बाबू थे एक आदर्श के प्रतिमूर्ति

स्व. अनिरूद्ध बाबू

स्मृति शेष स्व. अनिरूद्ध बाबू

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ

बांका जिले का कटोरिया प्रखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है जहां पहाड़ों और झरनों के साथ-साथ घने फलदार वृक्षों की शोभा प्राकृतिक सौंदर्य ताको और चार चांद लगा देता है ।कटोरिया प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित मुक्ति निकेतन स्थान इसी का एक सजीव उदाहरण है ।जहां अनेकानेक फलदार वृक्षों के साथ साथ औषधीय पौधों से युक्त बड़ा ही मनोरम प्राकृतिक शोभा से परिपूर्ण है । मुक्ति निकेतन के संत स्वर्गीय अनिरुद्ध बाबू जन-जन के आदर्श थे.1.1.1949 को जन्म लिए एक संत ने सुदूर जंगली क्षेत्र कटोरिया में शिक्षा का दीपक जलाया ।जिसके प्रकाश की लौ से संपूर्ण इलाका प्रकाशित हो रहा है। जहां आज कई उच्च पदों पर आसीन होकर इनके शिष्य पदाधिकारियों के रूप में अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं । ऐसे साक्षात प्रतिमूर्ति को शत शत नमन शत शत नमन ।स्वर्गीय अनिरुद्ध बाबू के अंदर ज्ञान और विद्वता का अथाह सागर समाहित था . मृदुभाषी और चेहरे पर शांत भाव और सामने वाले का उत्साहवर्धन करने का एक अलग ही गुण इन में समाहित था ।जिस कारण अनिरुद्ध बाबू मुक्ति निकेतन के पितामह कहलाते थे।

दिवंगत अनिरुद्ध सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते सांसद।

23.11.2022 की रात मुक्ति निकेतन के लिए एक काली रात साबित हुई ।जहां के संत अनिरुद्ध बाबू सदा के लिए हम सवों को छोड़ बहुत दूर चले गए। उनके निधन की सूचना मिलते ही संपूर्ण इलाका शोक में डूब गया ।दूर-दूर से इनके शिष्य अंतिम दर्शन हेतु मुक्ति निकेतन पहुंचने लगे ।जनप्रतिनिधियों, सांसद विधायकों ने भी मुक्ति निकेतन आकर इनके अंतिम दर्शन किए इनके आदर्शों और पद चिन्हों पर चलते हुए इनके सुपुत्र डॉ चिरंजीव कुमार आज मुक्ति निकेतन संस्था के सचिव हैं। जिन्हें अपने पिता के आशीर्वाद से निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए नित नये ऊंचाइयों को छूना है। शत शत नमन शत शत नमन शत शत नमन संत स्वंअनिरुद्ध बाबू को।

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

आशा देवी

उप मुख्य पार्षद

नगर पंचायत अमरपुर

प्रदीप कु. साह उर्फ पप्पू

वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 10

नगर पंचायत अमरपुर बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

बिनय प्रसाद यादव

सीटी मेनेजर

नगर परिषद बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हरे राम प्रसाद

जिला सांख्यिकी

पदाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अशोक कु. मिश्रा

लोक पाल

मनरेगा बांका

चर्चित बिहार परिवार की ओर से समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

समस्त देशवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ संजय मयूख

राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी

प्रवक्ता,विधान पार्षद

एमएलसी, भाजपा

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

संतोष कु. सिंह

अध्यक्ष

नगर परिषद, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

निवेदक

विनीता प्रसाद

उपाध्यक्ष, नगर परिषद, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चिरंजीव कुमार

निदेशक चाईल्ड लाईन, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. प्रभा रानी

महिला चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोड्डा (झारखंड)

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

वैद्यनाथ सिंह

जिला निबंधन पदाधिकारी, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

कुमार रंजन

जिला खनन पदाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अंगद प्रसाद लोहरा

उप निर्वाचन पदाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विष्णु देव प्रसाद रंजन

जिला कृषि पदाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अवधेश कुमार

जिला खनन निरीक्षक बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

हरिओम ओझा

खान निरीक्षक बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अनंत कुमार

डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अजय कुमार

कार्यक्रम पदाधिकारी धोरैया-बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मो.जावेद कमाल

कार्यक्रम पदाधिकारी बाराहाट बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

संजय कुमार किस्कु

जिला मत्स्य पदाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दीनानाथ सिंह

कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ संजय कुमार

प्रखंड विकास पदाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अमित कु. रंजन

अंचलाधिकारी बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

राकेश कुमार

प्रखंड विकास पदाधिकारी चांदन, जिला- बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अरुण कुमार

M.V.I बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ लक्ष्मण पंडित
एम.बी.बी.एस.
एम.एस. सर्जरी
सदर, अस्पताल, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अभय कुमार घोष
प्रभारी प्रधान लिपिक
प्रखंड कार्यालय
बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सुनील भारती
निम्न वर्गीय
लिपिक प्रखंड
कार्यालय, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अंजनी राम
उच्च वर्गीय लिपिक
जिला नजारत
बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

आचार्य रघुनंदन शास्त्री
आवासीय मार्शल
एकेडमी, खेसर, बांका,
मो.:8002850364

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. सरयू प्रसाद यादव
अध्यक्ष कुसाहा
वन समिति
जिला- बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ मौलेश्वरी सिंह विद्याभूषण
M.H.M.B.B.S.
(Darbhanga) R.M.P.H.
(Patna), D.C.P. (Ranchi)
Regd. No. 16261 दुधारी
बांका, मो. 9955601568

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ बलराम मंडल
जिला कृषि पदाधिकारी
बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रंजित कु. शर्मा
प्रो.शक्ति ग्लास हाउस
न्यू मार्केट कचहरी रोड, बांका,
8084789834

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

उत्तम कुमार
बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

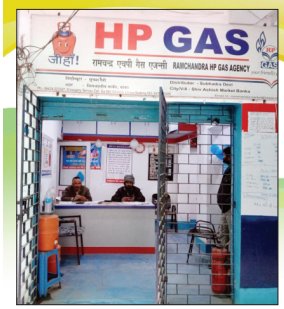

रामचन्द्र गैस एजेंसी
शिव आशीष
मार्केट, बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

इंडेन गैस एजेंसी
कटोरिया रोड
बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मासूक अंसारी
वार्ड पार्षद, वार्ड नं - 15
कटोरिया नगर पंचायत
बांका

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अशोक कुमार झा
उच्च वर्गीय लिपिक
जिला जनसंपर्क कार्यालय
बांका